● वर्ष-3
● अंक-77
रायपुर, मंगलवार
07 नवंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› अंजोरा जो दो विधानसभा ...

कांग्रेस और भ्रष्टाचार, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं: नड्डा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव (जशपुर) तथा लैलूंगा एवं छाल (रायगढ़) में आयोजित विशाल जनसभाओं में दिए गए उद्बोधन के मुख्य बिंदु कांग्रेस पार्टी का मतलब है - लूट, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, धोखा, विनाशकारी नीति और परिवारवाद (वंशवाद)। यही कांग्रेस की पहचान है। जहां कांग्रेस होगी, वहां भ्रष्टाचार होगा।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज सोमवार को छत्तीसगढ़ के हाईस्कूल मैदान, पत्थलगांव (जशपुर) में विशाल जनसभा, लैलूंगा (रायगढ़) में रथ यात्रा सभा और छाल, रायगढ़ (धरमजयगढ़ विधानसभा) में आयोजित विशाल चुनावी रैली को संबोधित किया और छत्तीसगढ़ की जनता से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को सत्ता से हटा कर विकास के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार बनाने की अपील की।

श्री नड्डा ने छत्तीसगढ़ की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि चुनाव की बेला है। आप सभी लोगों को 17नवंबर को अपने भविष्य का फैसला करना है। आप सभी लोगों को इस क्षेत्र के विकास को दृष्टिगत रखते हुए और विकास की चिंता एवं चर्चा करते हुए अपना निर्णय लेना है। इस चुनाव में एक तरफ भ्रष्टाचार और घोटालों में डूबी कांग्रेस है, तो वहीं दूसरी तरफ जनकल्याण के प्रति समर्पित भाजपा है। एक ओर विकास के कामों को आगे बढ़ाने वाली भाजपा है तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ का नुकसान करने वाली कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भ्रष्टाचार और घोटालों में डूबी कांग्रेस की बजाय सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को अपना आदर्श

मानने वाली भाजपा को जनता की सेवा का अवसर देने का मन बना लिया है।

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कांग्रेस के प्रत्याशी पर सवाल करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार ने यहाँ एक भी ईंट लगाई हो तो कांग्रेस इसका ब्यौरा दें। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही जनता के हितों की रक्षा की है, उनकी तरक्की के बारे में सोचा है और राज्य को विकास से जोड़ने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी का मतलब है - लूट, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, धोखा, विनाशकारी नीति और परिवारवाद (वंशवाद)। यही कांग्रेस की पहचान है। जहां कांग्रेस होगी, वहां भ्रष्टाचार होगा। कांग्रेस और भ्रष्टाचार, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब है विकास, तरक्की, लोगों की सरकार, कार्यकर्ताओं का सम्मान, जनहित, विकास को आगे बढ़ाना। अब एक तरफ भाजपा है जो दिन-रात जनता की चिंता करती है जबकि दूसरी तरफ है भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीतियों वाली कांग्रेस पार्टी जो केवल और केवल लूट की चिंता करती है। न आकाश छोड़ा, न जल छोड़ा, न पाताल छोड़ा, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया है।

श्री नड्डा ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पनडुब्बी घोटाला, कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और मनरेगा जैसे सभी बड़े घोटाले हुए। कांग्रेस की बघेल सरकार ने अपने शासन में केवल एक बात की गारंटी दी और वो है लूट, धोखा और भ्रष्टाचार। इस सरकार में ?2661 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, ?5000 का चावल घोटाला हुआ, ?540 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। गौठान में भी ?1300 करोड़ का घोटाला, ?234 करोड़ का ह्रस्ष्ठ घोटाला हुआ। टीचर्स ट्रांसफर घोटाले की कड़ियाँ भी भूपेश बघेल के ह्रस्ष्ठ से जुड़ी मिली, उनके घर से इन घोटालों सें जुड़े अवैध लेन देन की राशि बरामद हुई और जिसका परिणाम ये है कि वे बीते डेढ़ साल से जेल की हवा खा रहें हैं। हमने तरह-तरह के घोटाले सुने थे लेकिन भूपेश सरकार ने तो गोबर में भी घोटाला कर दिया। इन्होंने भगवान महादेव को भी नहीं छोड़ा, सत्ता में आने के लिए ?6,000 करोड़ का सट्टा घोटाला कर दिया। खुद आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वह भूपेश बघेल को पैसा देने आया था।

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार घोटालों, लूट और धोखों की सरकार है। कांग्रेस ने जनता से वादा किया था कि बिजली का बिल माफ करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा किया था लेकिन नहीं दिया। बघेल सरकार ने 50 हजार आदिवासी टीचर की भर्ती का वादा किया था लेकिन ये वादा भी अधूरा रहा। बघेल सरकार ने साल में 4 फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, नहीं दिया। महिलाओं को ?500 प्रति माह देने का वादा भी कांग्रेस सरकार का था, वह भी नहीं मिला।

कांग्रेस इसी तरह से जात-पात करती है: रामेश्वर तेली

रायपुर। भाजपा के पक्ष में प्रचार करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस की जातिगत जनगणना की घोषणा पत्र पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी तरह से जात-पात ही करती है, लेकिन हमारी पार्टी की घोषणा पत्र में जो कहा गया उसे मैं दोहराना चाहता हूं, जो हमने कहा है कि उसे हम पूरा करेंगे.महादेव सट्टा एप को लेकर मीडिया में चल रहे वायरल वीडियो पर केंद्रीय राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि यहां सट्टा तो नहीं होना चाहिए. पार्टी की तरफ से बयान आया तो मेरा बोलना उचित नहीं है. हां, मुख्यमंत्री अगर इसमे इंवॉल्व हैं, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए.

छत्तीसगढ़ की तरह अन्य 5 राज्यों में भी 21 क्विंटल धान खरीदने के सवाल पर रामेश्वर तेली ने कहा कि हर जगह के अपने-अपने इश्यू होते हैं. छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो यहां धान के बारे मे हैं. मैं तो असम से हूँ, वहां चाय के बागान है, तो वहां चाय के बारे में बात होगी. हर जगह अपने-अपने इश्यू हैं.विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने मीडिया से चर्चा में बताया कि दो विधानसभाओं में जाऊंगा. दो रोड शो भी करेंगे और दो बड़े जनसभा करेंगे. पूरा विश्वास है इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी. यह नहीं कह सकता कि कितनी सीट हमें मिलेंगी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी डबल इंजन की सरकार बनेगी.

व्यापार जगत की हर समस्या का समाधान करेगी भाजपा: मांडविया

रायपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव सह प्रभारी मनसुख भाई मांडविया ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी एवं पदाधिकारी ने श्री मांडविया से चर्चा करते हुए अपनी बातें रखी।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया ने कहा कि भारत की संस्कृति और परंपरा में व्यापारी और व्यवस्था करने वाले शासक आपस में मिल बैठकर समस्याओं का समाधान कर देश की अर्थव्यवस्था और वितरण प्रणाली को मजबूत करते आए हैं। यह चाणक्य काल से भारत में प्रथा रही है। उन्होंने कहा कि आज चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने मेरे सामने जो समस्याएं रखी हैं, कुछ जीएसटी से संबंधित हैं, कुछ व्यापार उद्योग से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि विकास के संबंध में चेंबर के सुझाव आए हैं, आपने मुझे लिखकर भी सारी चीज दी है। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा।

छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के 12 लाख व्यापारी परिवार के सभी सदस्य चुनाव में वोट देने जाएं, इसके लिए हम जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और आशा है कि सभी व्यापारी परिवार के सदस्य वोट देने जरूर जाएंगे।

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यालय में इस कार्यक्रम के अवसर पर चेंबर के संरक्षक गण असुदामाल जी, महेंद्र धारीवाल, हनुमान प्रसाद अग्रवाल, महामंत्री अजय भसीन, शंकर बजाज , जितेंद्र भाई दोशी, निलेश मूंदड़ा, वासु मखीजा, शंकर बजाज एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता, शहरी जिला भाजपा अध्यक्ष जयंती पटेल, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक सुभाष अग्रवाल, व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सतीश सुभानी एवं चेंबर के प्रमुख पदाधिकारी गण उपस्थित रहे।

आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान

रायपुर। छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 के पहले चरण के लिए मतदान मंगलवार, 7 नवंबर को होने वाला है। पहले चरण के मतदान में 90 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में 40 लाख से अधिक मतदाता 5,304 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 20 सीटों के साथ-साथ 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा के लिए भी मंगलवार को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग और राजनांदगांव सहित चार अन्य जिलों के 20 सीटों में होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पहले चरण के मतदान में राज्य के 40,78,681 मतदाता 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन उम्मीदवरों में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और बस्तर के सांसद दीपक बैज, कांग्रेस सरकार के तीन मंत्री, भाजपा की ओर से चार पूर्व मंत्री और एक पूर्व आईएएस अधिकारी शामिल हैं।

मिजोरम में भी डाले जाएंगे वोट

छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान दो स्लॉट में होगा। इन दो अलग-अलग स्लॉट में दस-दस विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। पहला स्लॉट सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक और दूसरा स्लॉट सुबह 7 बजे से 3 बजे तक है। पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है, उनमें से ज्यादातर सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। इनमें बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कवर्धा और राजनांदगांव जिले शामिल हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। राज्य में वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर मतदान होना है उनमें से 12 अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए जबकि एक अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए आरक्षित है। 2018 के चुनाव में भाजपा को इन 20 सीटों में से 18 पर हार का सामना करना पड़ा था।

मिजोरम में मतदान

मिजोरम में मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 8.57 लाख से अधिक मतदाता 174 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मधुप व्यास ने कहा कि मिजोरम के सभी 1,276 मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे मतदान शुरू होगा और शाम चार बजे तक जारी रहेगा। मतगणना तीन दिसंबर को

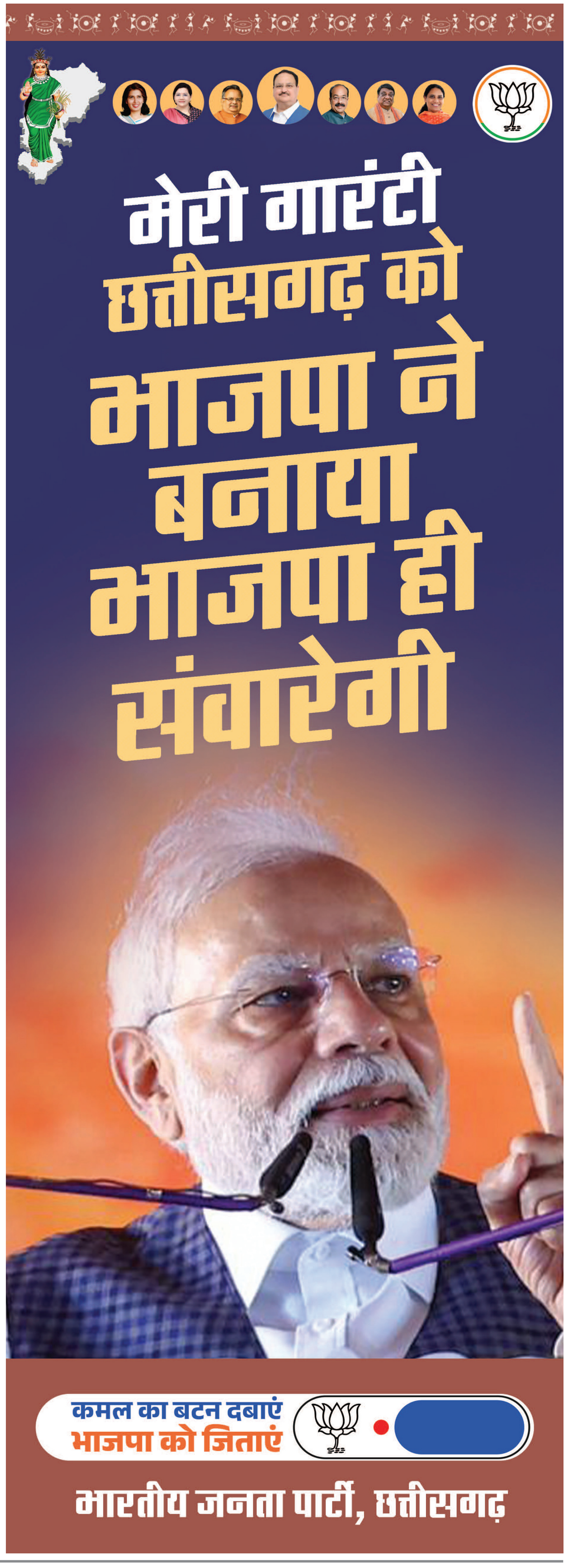

पहले चरण का मतदान आज, भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला

पहले फेज के तहत बस्तर की 12 सीटों पर वोटिंग आज, नक्सल प्रभावित बस्तर में सुरक्षाबलों ने सभी 12 सीटों पर सुरक्षा पुख्ता किया

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत कुल 20 सीटों पर मतदान होना है। 7 नवंबर को मतदान संपन्न होंगे और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। विधानसभा सीटवार मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। आम आदमी पार्टी, जोगी कांग्रेस, बीएसपी और गोंगपा के अलावा सीपीआई भी चुनाव लड़ रही है। लेकिन मेन फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच बताई जा रही है।

पहले फेज के तहत बस्तर की 12 सीटों पर वोटिंग 7 नवंबर को होगी। विधानसभा सीट वार उम्मीदवारों पर नजर डालते हैं। जगदलपुर सीट से बीजेपी ने किरण सिंह देव को उम्मीदवार बनाया है। जबकि कांग्रेस की तरफ से जतिन जायसवाल को मैदान में उतारा गया है। बस्तर सीट से बीजेपी ने मनीराम कश्यप को उम्मीदवार बनाया है। जबकि कांग्रेस की तरफ से लखेश्वर बघेल मैदान में हैं। नारायणपुर से बीजेपी के कदावर नेता केदार कश्यप चुनावी फाइट में हैं। जबकि कांग्रेस की तरफ से चंदन कश्यप मुकाबले में हैं। कांकेर से बीजेपी की ओर से आशाराम नेताम हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के शंकर ध्रुवा से हो रहा है।

कोंडागांव से बीजेपी ने लता उसेंडी को मैदान में उतारा है। जबकि कांग्रेस ने मोहनलाल मरकाम पर दाव खेला है। केशकाल से बीजेपी ने पूर्व आईएएस नीलकंठ टेकाम को टिकट दिया है। जबकि कांग्रेस ने संतराम नेताम पर भरोसा जताया है। इसी तरह दंतेवाड़ा से बीजेपी की तरफ से चेतराम अरामी मैदान में हैं। जबकि

कांग्रेस की तरफ से छविंद्र कर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। अंतागढ़ से बीजेपी ने विक्रम उसेंडी पर दाव खेला है। तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट से रूप सिंह पोटाई को चुनावी मैदान में उतारा है। भानुप्रतापपुर से बीजेपी की ओर से गौतम उईके मैदान में हैं जबकि कांग्रेस की ओर से सावित्री मंडावी चुनाव लड़ रहीं हैं।

सुकमा की कोंटा विधानसभा सीट से बीजेपी ने सोयम मुका को उतारा है। जबकि कांग्रेस ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा को टिकट दिया है। चित्रकोट में बीजेपी की ओर से विनायक गोयल मैदान में हैं। जबकि कांग्रेस की ओर से पीसीसी चीफ दीपक बैज चुनावी अखाड़े में हैं। बीजापुर की बात करें तो बीजेपी ने पूर्व मंत्री महेश गागड़ा पर दांव खेला है। जबकि कांग्रेस की ओर से मौजूदा विधायक विक्रम शाह मंडावी मैदान में हैं।

बस्तर की 12 सीटों के बाद अन्य 8 सीटों पर नजर डालते हैं। जहां सात नवंबर को मतदान होने हैं। उनमें सबसे हाईप्रोफाइल सीट राजनांदगांव हैं। यहां से पूर्व सीएम रमन सिंह चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने नामांकन भी भर दिया है। रमन सिंह के सामने कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है। इसके अलावा अन्य सीटों की बात करें तो मोहला मानपुरस से बीजेपी ने संजीव साहा को टिकट दिया है। उनके सामने इंद्र शाह मंडावी चुनावी फाइट में हैं। जबकि खुज्जी से बीजेपी ने गीता घासी साहू को उम्मीदवार बनाया है। यहां उनकी टक्कर कांग्रेस के भोलाराम साहू से हो रही है। पंडरिया से बीजेपी ने भावना बोहरा को उम्मीदवार बनाया है। यहां से कांग्रेस ने नीलकंठ चंद्रवंशी को मैदान में उतारा है। कवर्धा से बीजेपी ने विजय शर्मा पर भरोसा जताया है। जबकि कांग्रेस की ओर से मोहम्मद अकबर मैदान में हैं। खैरागढ़ से बीजेपी ने विक्रांत सिंह को मैदान में उतारा है। उनकी टक्कर कांग्रेस की यशोदा वर्मा से हो रही है। डोंगरगढ़ से बीजेपी ने विनोद खांडेकर पर भरोसा जताया है। जबकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ हर्षिता स्वामी बघेल को टिकट दिया है। डोंगरगांव से बीजेपी के भरतलाल वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि कांग्रेस के दिलेश्वर साहू मैदान में हैं।

छत्तीसगढ़ के पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव के लिए सारी तैयारियां चौकस कर ली गई है। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नक्सल प्रभावित बस्तर में सुरक्षाबलों ने सभी 12 सीटों पर सुरक्षा पुख्ता कर ली है। चुनाव अधिकारी भी हर सीट पर नजर रख रहे हैं। नामांकन का दौर जारी है। दूसरी तरफ अन्य 8 सीटों पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। कवर्धा और राजनांदगांव से लगे सभी जिलों की सीटों पर चुनाव अधिकारी एक्टिव है। जिला प्रशासन की ओर से सारे एहतियात बरते जा रहे हैं।

भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह का कांग्रेस पर करारा प्रहार

भरतपुर-सोनहत। पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान मंगलवार को होना है। 20 सीटों पर मतदान के बाद बाकी बची सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी और सत्तारुढ़ कांग्रेस पार्टी दोनों ही दल चुनाव प्रचार में लगातार लगे हैं। पहले बीजेपी ने अपना घोषणापत्र जारी किया फिर कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया। भरतपुर सोनहत से बीजेपी प्रत्याशी बनीं रेणुका सिंह ने सरकार पर अवैध खनन को संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वो यहां से विधायक बनीं तो अवैध रेत खनन पर पूरी तरह से रोक लगा देंगी। जो भी अवैध खनन करता पकड़ा जाएगा उसपर कड़ी कार्रवाई करेंगी। रेणुका सिंह ने दावा किया कि अगर वो विधायक बनती हैं तो जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही काम करेंगी। भाजपा ने इस बार भरतपुर सोनहत सीट से कद्दावर बीजेपी नेता रेणुका सिंह को मैदान में उतारा है। रेणुका सिंह ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि जिले में जो भी बालू माफिया हैं और अवैध खनन कर रहे हैं उनपर शिकंजा कसा जाए। जनता इन बालू माफिया से परेशान है जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता होगी की माफिया का अंत हो। चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, जनता का मूड किसके पक्ष में जाएगा ये तो मतदान के बाद जब वोटों की गिनती होगी तो नतीजों से पता चलेगा। पर इतना तो तय है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस को जहां कका और बाबा की जोड़ी पर भरोसा है वहीं बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं के सहारे मैदान में उतरी है। अब देखना ये है कि जनता किसके दावों पर कितना भरोसा करती है।

बिलासपुर विधानसभा में कई प्रत्याशी खुद के लिए नहीं कर पाएंगे मतदान

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई ऐसे प्रत्याशी है जिनका नाम मतदाता सूची में किसी और जगह है और वह किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे प्रत्याशी अपने खुद के लिए अपने मत का उपयोग नहीं कर पाएंगे। बिलासपुर संभाग की बात करे तो कांग्रेस, भाजपा, बसपा, जेसीसीजे सहित गोंगपा ने प्रत्याशियों को ऐसे विधानसभाओं से टिकट दिया है जहां से वो अपना वोट अपने पार्टी के दूसरे उम्मीदवार को देंगे और अपने लिए दूसरों से वोट मांगेंगे।

बिलासपुर संभाग की अगर बात करें तो बिलासपुर संभाग में 24 विधानसभा है, जिनमें सैकड़ों प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीयों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस और भाजपा के कई प्रत्याशी अपने लिए अपना मतदान नहीं कर पाएंगे। पार्टी उन्हें जातिगत समीकरण और पार्टी के प्रभावित क्षेत्र से चुनाव लड़वा रही हैं इस वजह से वह जनता से खुद के लिए मतदान करने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन अपना वोट किसी और को देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका नाम दूसरे विधानसभा की मतदाता सूची में है और वह दूसरे विधानसभा से चुनाव लड़ रहे है।

बिलासपुर विधानसभा

1 बेलतरा विधानसभा- भाजपा के प्रत्याशी सुशांत शुक्ला और कांग्रेस प्रत्याशी विजय केशरवानी का बिलासपुर विधानसभा की मतदाता सूची में नाम है और वह बेलतरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 कोटा विधानसभा- भाजपा के प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जूदेव का जशपुर विधानसभा की मतदाता सूची में नाम है। कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव का बिलासपुर विधानसभा की मतदाता सूची में नाम है और वह कोटा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। रेणु जोगी का नाम भी अन्य विधानसभा में है और वह जेसीसीजे की टिकट से कोटा से चुनाव लड़ रही है। 3 तखतपुर विधानसभा- भाजपा के प्रत्याशी धर्मजीत सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी रश्मि सिंह का बिलासपुर विधानसभा की मतदाता सूची में नाम है और वह तखतपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। 4 मस्तूरी विधानसभा- भाजपा के प्रत्याशी कृष्णमूर्ति बांधी का बिलासपुर विधानसभा की मतदाता सूची में नाम है और वह मस्तूरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। 5 बिल्हा विधानसभा- आप पार्टी के प्रत्याशी जसबीर सिंह चावला का बिलासपुर विधानसभा की मतदाता सूची में नाम है और वह बिल्हा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। 6 मुंगेली जिला के लोरमी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम बिलासपुर विधानसभा में है। वह लोरमी से चुनाव लड़ रहे हैं। जेसीसीजे की टिकट से चुनाव लड़ने वाले सागर सिंह बैंस मुंगेली विधानसभा के मतदाता है और लोरमी से चुनाव लड़ रहे हैं।

कवर्धा चुनाव के लिए चुनाव सामग्री के साथ मतदान दल रवाना

कवर्धा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के प्रथम चरण का मतदान 7 नवंबर को 20 सीटों में होने जा रहा है। जिसमें कबीरधाम जिले के पंडरिया और कवर्धा विधानसभा भी शामिल हैं। इस विधानसभा में 804 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिसके लिए 3216 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कवर्धा और पंडरिया विधानसभा चुनाव के लिए लिए सभी मतदानकर्मियों को चुनाव सामग्री के साथ रवाना किया गया। सभी मतदान दल को स्ट्रॉन्ग रूम आदर्श कृषि मंडी तालपुरा में चुनाव साम्रगी बांटी जा रही है।

कवर्धा विधानसभा में 110 संवेदनशील मतदान केंद्र है और 11 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र हैं। जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिए 4 हजार जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। जिन्हें अपने-अपने निर्धारित ड्यूटी स्थान पर रवाना किया जा रहा है।

कवर्धा विधानसभा-कुल मतदान केंद्र 411, कुल मतदाता 03 लाख 31 हजार 407, महिला मतदाता 01लाख 66 हजार 717, पुरुष मतदाता 01 लाख 74 हजार 687, दिव्यंग मतदाता 2441, युवा मतदाता 15 हजार 802, थर्ड जेंडर 03। **पंडरिया विधानसभा**- कुल मतदाता केंद्र 393, कुल मतदाता 03 लाख 16 हजार 142, महिला मतदाता 01 लाख 58 हजार 493, पुरुष मतदाता 01 लाख 57 हजार 649, दिव्यंग मतदाता 3102, युवा मतदाता 14 हजार 588, थर्ड जेंडर 0। कवर्धा में कांग्रेस के प्रत्याशी मंत्री मोहम्मद अकबर है। भाजपा ने यहां से विजय शर्मा को टिकट दिया है। पंडरिया विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी भावना बोहरा है कांग्रेस ने यहां से नीलकंठ चंद्रवंशी को चुनाव मैदान में उतारा है।

सूरजपुर के ग्रामीणों ने मतदान करने से किया इनकार

सूरजपुर। जिले के भटगांव विधानसभा क्षेत्र के भैयाथान ब्लॉक का गांव सत्यनगर आजादी के 70 साल बाद भी उपेक्षा का शिकार है। गांव में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव हैं। जिसके लिये गांववालों ने विधायकों और सांसदों को जिम्मेदार ठहराते हुए मतदान का बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार के ऐलान से प्रशासन सकते में आ गया है।

दुर्गम जंगलों से घिरे सत्यनगर गांव के मतदाताओं ने चुनाव आते ही बैठक आयोजित की थी। बैठक में उन्होंने गांव का विकास न हो पाने के लिए सीधे तौर पर निर्वाचित विधायकों और सांसदों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले कई सालों से पुल और सड़क बनाने की मांग की थी, जिस पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इससे नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है।

ग्रामीण ने कहा ग्राम पंचायत सत्यनगर सड़क और पुल न बनने से लोगों को 25 से 30 किमी दूर राशन लेने पैदल जाना पड़ता है। बारीश के दिनों में हमारे अलावा स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानी होती है। कई दिन तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं।

भैयाथान ब्लॉक के जनपद सदस्य अभय प्रताप सिंह ने बताया कि स्कूल और पुलिया का टीका पीडब्ल्यूडी द्वारा कर दिया गया है। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण अभी तक यह पुल-पुलिया नहीं बन पाया है। जिससे ग्रामीणों में इसे लेकर काफी नाराजगी है। हम जनप्रतिनिधि भी इन ग्रामीणों के साथ खड़े हैं।

लगभग 300 मतदाताओं वाले इस गांव से विकास कोसों दीर है। ग्रामीणों ने सड़क और पुल नहीं, तो मतदान नहीं का नारा बुलंद कर दिया है। ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने पत्र के सूरजपुर जिला प्रशासन को भी दी है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

दंतेवाड़ा में ग्रेनेड विस्फोट, हिमाचल के जवान की मौत

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में रविवार को चुनावी ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान की ग्रेनेड विस्फोट में मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक विस्फोट उस वक्त हुआ, जब ड्यूटी के लिए कटेकल्याण पुलिस थाने में तैनात बीएसएफ की 70वीं बटालियन की एक टीम तलाशी अभियान शुरू करने वाली थी। गश्त के लिए दल थाना परिसर से बाहर जा रहा था, तभी हेड कांस्टेबल बलबीर चंद द्वारा पहनी थैली में रखा हथगोला फट गया। घटना में बलवीर चंद गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत दंतेवाड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया,जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बलवीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के राजा का तालाब नेरना गांव के रहने वाले थे और उनके परिवार के सदस्यों को घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है। दरअसल दंतेवाड़ा उन 20 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, जहां 7 नवंबर को पहले चरण में मतदान होगा।

दयालदास बघेल का कांग्रेस पर हमला

बेमेतरा। नवागढ़ भाजपा कार्यालय में प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व नवागढ़ के भाजपा प्रत्याशी दयालदास बघेल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूर्व में विधानसभा चुनाव में गंजाजल की कसम खाकर शराब बंदी की बात कही थी जो अमल नहीं हुआ। बघेल ने कहा कि कांग्रेस अब बछिया की पूंछ पकड़कर कसम भी खा लें तो यहां की जनता उनकी बातों पर विश्वास नहीं करने वाली है। पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात कही है। लेकिन कांग्रेस ये राशि किश्तों में देगी। जबकि भाजपा 3100 रुपये नकद एक मुश्त किसानों को देगी। दयाल दास ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं के लिए 12 हजार प्रति वर्ष देने की घोषणा की है जिससे छत्तीसगढ़ की महिलाओं में खुशी की लहर है। पूर्व कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि भूपेश सरकार ने पिछले किए हुए वादे अब तक पूरे नहीं किया और अब नए वादे कर दिए। शराबबंदी की बात भी जुमला निकली।

नक्सलियों ने कांग्रेस के दो नेताओं को जान से मारने का लगाया बैनर फेंके पर्चे

नारायणपुर। जिले के अलग-अलग इलाकों में नक्सलियों ने धमकी वाला बैनर लगाया और पर्चा फेंका है। नक्सलियों द्वारा एक बैनर जिला मुख्यालय के अंदर पहाड़ी मंदिर के पास लगया है, जिसमें दो कांग्रेस नेताओं बिसेल नाग मांझी एवं अमित भद्रा को जान से मारने की धमकी दी गई है, इससे इलाके में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के ठीक एक दिन पहले आज सोमवार को नक्सलियों ने भाजपा नेता की हत्या के बाद अब कांग्रेस नेताओं को मौत के घाट उतारने की धमकी भरा बैनर लगया एवं पर्चा फेंका है। यह ममला नारायणपुर थाना क्षेत्र समेत अलग-अलग इलाकों का है।

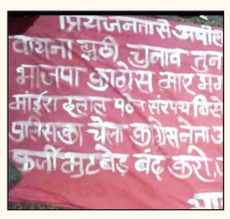

बांस छींद से सजा इको फ्रेंडली बूथ

कांकेर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को बूथ तक लाने प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए पिंक बूथ, संगवारी बूथ बनाए गए थे। इस बार निर्वाचन आयोग इससे दो कदम आगे बढ़ते हुए इको फेंडली बूथ, आदर्श मतदान केंद्र और रेनबो बूथ बनाया है। ये तीनों मतदान केंद्र चुनाव से पहले ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तीन इको फ्रेंडली मतदान केंद्र अंतागढ़ के सोहगांव, भानुप्रतापपुर के धनगुडरा और कांकेर के चिवरांज में तैयार किए गए हैं। इन मतदान केंद्रों को वन विभाग ने तैयार किया है। जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं जैसे बांस, छींद के पत्तों का उपयोग किया है। वन विभाग ने इन केंद्रों की तैयारी में प्राकृतिक वस्तुओं जैसे बांस, छींद के पत्तों का उपयोग किया है। प्रवेश द्वार, प्रतीक्षालय, सेल्फी कॉर्नर बनाने बांस और पत्तियों का उपयोग किया गया है। पानी पीने मिट्टी के बर्तन रखे गए हैं। कांकेर की तीनों विधानसभा में 30 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

बीजापुर में चुनाव से पहले गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग

बीजापुर। बीजापुर में मंगलवार को विधानस चुनाव होना है। उससे पहल बड़ी आगजनी की घटना जिले में हुई हैं। यहां स्थित सरकारी गारमेंट फैक्ट्री में बड़ी आग लग गई। जिससे लाखों रुपये के कपड़े जलकर खाक हो गए। ये सरकारी गारमेंट कंपनी माँझीगुड़ा में स्थित है। जहां रात 3 बजे आगजनी की घटना लग गई। देर रात आग लगने से आग फैल गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। कपड़े में आग लगने के कारण फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। डीएसपी तुलसीराम ने बताया कि मांझीगुड़ा स्थित गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। डीएसपी ने शरारती तत्वों द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम देने की आशंका जताई। जांच के बाद मामले का खुलासा होने की बात कही। फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है कि नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है।

जगदलपुर विधानसभा सीट में मारवाड़ी समाज विनिंग फैक्टर

जगदलपुर। बस्तर संभाग में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। कहते हैं कि बस्तर के रास्ते ही छत्तीसगढ़ सियासत का रास्ता तय होता है। बस्तर के 12 विधानसभा सीटों में जगदलपुर विधानसभा सीट अनारक्षित है। जगदलपुर विधानसभा सीट साल 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले तक आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट थी। हालांकि साल 2008 के विधानसभा चुनाव के बाद इस सीट को सामान्य सीट घोषित कर दिया गया। 2018 में जगदलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रेखचंद जैन ने जीत दर्ज की। इस सीट पर इससे पहले पिछले 10 सालों से भाजपा का राज था।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जगदलपुर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। कांग्रेस ने पूर्व महापौर रहे जतिन

जायसवाल को जगदलपुर सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं भाजपा ने भी जगदलपुर से पूर्व महापौर रहे किरण देव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस बार जगलपुर सीट पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के पूर्व महापौर के बीच होगा।

जगदलपुर विधानसभा सीट अनारक्षित है। यहां करीब 60 से 65 फीसदी आबादी सामान्य लोगों की है। इस सीट पर माहरा, धुरवा, मुरिया, माड़िया, सुंडी, मारवाड़ी लोग भी रहते हैं। यहां 35 से 40 फीसदी आबादी आदिवासियों की है। इस विधानसभा में पार्टियों का फोकस सामान्य कैटेगिरी के लोगों पर रहता है। माहरा समाज के लोगों की संख्या अधिक होने के कारण साल 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने माहरा जाति के शामू कश्यप को अपना प्रत्याशी बनाया था।

मुद्दे और समस्याएं- जगदलपुर विधानसभा में मुख्य मुद्दा मूलभूत सुविधाओं का है। अंदरूनी इलाकों में आजादी के 75 साल बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। विधानसभा में विधायक निर्वाचित होने के बाद भी गांव तक नहीं पहुंचते हैं। यहां के ग्रामीणों की समस्या को नहीं सुनते। यही कारण है कि बिजली, पानी और सड़क की समस्या यहां सबसे अधिक है। जगदलपुर विधानसभा के झीरम गांव की तस्वीर नहीं बदली है। आज भी ग्रामीण झरिया या पोखर का पानी पीने को मजबूर हैं। यहां स्थित नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का भी मुद्दा सबसे बड़ा है। बेरोजगारी की समस्या इस विधानसभा में अधिक देखने को मिलती है। बस्तर संभाग का एकमात्र जगदलपुर विधानसभा सीट अनारक्षित है। इस विधानसभा में सबसे अधिक सामान्य लोगों की जनसंख्या है, जिसमें मारवाड़ी समाज, माहरा समाज सहित अन्य समाज शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रत्याशी मारवाड़ी समाज से थे। इससे पहले भाजपा के प्रत्याशी संतोष बाफना इस विधानसभा से विधायक चुनकर आए थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में मारवाड़ी समाज के लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी रेखचंद जैन को अपना वोट दिया। जिसके कारण 27 हजार 440 वोट से रेखचंद जैन ने जीत दर्ज की।

कड़ी सुरक्षा में जा रहे हैं मतदान दल

जगदलपुर। सुकमा जिले में शांतिपूर्ण चुनाव कराना जिला प्रशासन के लिए चुनौती है, अब मौसम भी बड़ा बाधक बन रहा है। कोंटा विधानसभा के 42 मतदान केंद्र घोर नक्सल प्रभावित हैं, वहां मतदान दलों को सेना के हेलीकाप्टर से भेजा जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण दो दिन में मात्र 25 ही दल जा पाया। तीसरे दिन हेलीकाप्टर से मतदान दल को भेजा गया। बाकी 191 दलों को सुरक्षा बल के जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया।सुरक्षा में महिला कमांडो भी तैनात है।

वहीं सभी 233 मतदान दल कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केन्द्र के लिए रवाना होंगे। रविवार सुबह खराब मौसम होने के कारण सेना का एमआइ 17 हेलीकाप्टर देर से जिला मुख्यालय पहुंचा और दो बजे तक 10 मतदान दल को ही कैंप तक पहुंचा पाया। क्योंकि उसके बाद मौसम खराब होने के कारण हेलीकाप्टर ने उड़ान नहीं भरी। यही हाल शनिवार को भी था दो बजे तक 15 दल ही कैंप तक जा पाए। जबकि दो दिनों में 42 मतदान दल को

हेलीकाप्टर से भेजा जाना था। खराब मौसम ने जिला निर्वाचन की चिंता बढ़ा दी। साथ ही आज शाम तक लगभग सभी 233 मतदान दल मतदान केंद्र कड़ी सुरक्षा के साथ पहुंच जाएंगे और 7 नवंबर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूर्ण कर ली है। सुकमा जिले की एकमात्र विधानसभा सीट कोंटा, जहां 233 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें 40 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां महिला कमांडो भी सुरक्षा में तैनात रहेगी। वहीं 71 मतदान केंद्र में सीसीटीवी लगाई गई है।

संक्षिप्त समाचार

पिछले साल की तरह इस बार भी गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन

रायपुर। आमतौर पर दीपावली का त्यौहार पांच दिनों तक मनाया जाता है लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी छह दिन तक दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। सुख समृद्धि, वैभव का पर्व दीपावली यानी लक्ष्मी पूजा 12 नवम्बर को मनाया जाएगा, लेकिन दूसरे दिन गोवर्धन पूजा नहीं मनाया जाएगा क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि दो दिन पड़ रही है। ऐसे में दिवाली के अगले दिन स्नानदान अमावस्या होगी और 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या का संयोग रहेगा, जो तीर्थ स्थलों पर स्नान, पूजा पाठ के लिए विशेष शुभ रहेगा। पंडितों के अनुसार दीपावली पर्व की रात्रि व्यापिनी अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है, जिस दिन रात्रि में अमावस्या रहती है, उस दिन दीपावली पर्व होता है। इस बार अमावस्या तिथि दो दिन रहेगी। अमावस्या 12 नवंबर को दोपहर 2 बजकर 46 मिनट पर आएगी और अगले दिन 2 बजकर 58 मिनट तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को दीपावली पर्व मनाया जाएगा, वहीं 13 नवम्बर को स्नानदान की अमावस्या रहेगी। इस दिन सोमवार होने से सोमवती अमावस्या भी रहेगी। दीपावली उत्सव पिछले साल भी छह दिन का था। पिछले साल दिवाली के अगले दिन सूर्यग्रहण था, इसके चलते एक दिन बाद गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया गया था। इस बार भी 12 को दीपवली और 14 नवम्बर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा।

15 से होने वाली बीएससी नर्सिंग परीक्षा अब 22 से

रायपुर। विधानसभा चुनाव के कारण बीएससी नर्सिंग प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर की 15 नवंबर से होने वाली परीक्षा स्थगित हो गई है। इस संबंध में हेल्थ साइंस विवि ने अधिसूचना जारी कर दी है। स्थगित परीक्षा अब 22 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेगी। तीनों ही कक्षाओं की परीक्षा में 12 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं के शामिल होने की संभावना है। प्रदेश में सरकारी के 8 समेत नर्सिंग के कुल 145 कॉलेज है, जिसमें 115 कॉलेजों में बीएससी कोर्स चल रहा है। नर्सिंग में पिछले साल से सेमेस्टर प्रणाली से परीक्षा शुरू हुई है। पहले जारी रिजल्ट में महज 41 व दूसरी बार के रिजल्ट में 52 फीसदी छात्र-छात्राएं पास हुए थे। यानी जब एक साल में एक बार परीक्षा होती थी, तब रिजल्ट 60 फीसदी के आसपास आता था। सेमेस्टर प्रणाली का सिस्टम पूरे देशभर में हुआ है। विवि के अधिकारियों के अनुसार परीक्षा के लिए टाइम-टेबल सितंबर में घोषित किया गया था। तब विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी नहीं हुआ था। परीक्षा के लिए पहले ही केंद्र घोषित कर दिया गया था।

अबूझमाड़ की मलखंभ टीम ने टीवी शो में मारी बाजी, मुख्यमंत्री बघेल ने दी बधाई

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अबूझमाड़ के मलखंभ खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि टीवी शो के विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए लिखा है कि शानदार प्रदर्शन आप लोगों ने किया। कितनी खुशी की बात है और कितने गर्व की बात है आपने छत्तीसगढ़ का नाम देश के मानचित्र पर एक बार फिर से रोशन किया। अबूझमाड़ से निकली ये प्रतिभा अब किसी पहचान की मोहताज नहीं। आपकी प्रतिभा का आज पूरा छत्तीसगढ़ कायल है। आपकी जीत में पूरा छत्तीसगढ़ शामिल है। आपने अपनी जीत से जो गर्व का पल छत्तीसगढ़ के लोगों को दिया है उसे महसूस कर गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी इस जीत के लिए बधाई के पात्र हैं। सिर्फ मेरी ओर से नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से आपको बधाई है। निजी चैनल पर प्रसारित किए जाने वाले टैलेंट शो में कई राज्यों के धुरंधर खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी टीमों के साथ हिस्सा लिया था। पर आखिरी राउंड में बाजी छत्तीसगढ़ की मलखंभ की टीम ने मारा और ये साबित कर दिया कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। खिलाड़ियों की प्रतिभा और फाइनल में उनके कमाल को देखते हुए मुख्यमंत्री भी उनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक सके।

मिजोरम-छत्तीसगढ़ के पहले चरण का मतदान आज, चुनाव प्रचार पर लगी रोक

रायपुर/आइजोल। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर चुनाव प्रचार रविवार शाम को थम गया। इन दोनों राज्यों में मंगलवार, 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में शेष 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा।

छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग की 12 और राजनंदगांव क्षेत्र की 8 सीटों पर मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। 20 सीटों में से 10 पर सुबह सात बजे से दोपहर 3 बजे तक जबकि शेष 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। पहले चरण की 20 सीटों पर कुल 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा में है। पहले चरण में 40 लाख 78 हजार 681 मतदाता 5304 केंद्रों पर मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रचार के दौरान पीएम मोदी समेत भाजपा ने सट्टेबाजी एप घपले के बहाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व कांग्रेस पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने अपनी गारंटी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को मुख्य मुद्दा बनाया।

वहीं, मिजोरम में 40 विधानसभा सीटों के लिए 1276 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के 8,51,895 मतदाता 174 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट,

जोरम पीपुल्स मूवमेंट, कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला है। मिजो, जोरम और कांग्रेस ने सभी 40 जबकि भाजपा ने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी राज्य में चार सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। चुनाव में मणिपुर हिंसा का भी असर देखने को मिलेगा।

पहले चरण की हाई प्रोफाइल सीटों पर दिग्गजों के बीच मुकाबला

छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों के लिए सात नवंबर को होने वाले मतदान में पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह समेत उनके कैबिनेट के पांच पूर्व मंत्रियों और भूपेश सरकार के तीन मंत्रियों व एक सांसद व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की साख दांव पर है। प्रथम चरण में कुल 223 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें 198 पुरुष व 25 महिलाएं हैं। 20 में से 10 सीट पर नजर हैं जहां दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं।

- नारायणपुर से भाजपा प्रत्याशी केदार कश्यप के सामने कांग्रेस प्रत्याशी चंदन कश्यप
- कोंडागांव से भाजपा प्रत्याशी लता उसेंडी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी मोहनलाल मरकाम
- बीजापुर से भाजपा प्रत?याशी महेश गागड़ा के सामने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मंडावी
- अंतागढ़ से भाजपा प्रत्याशी विक्रम उसेंडी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी रुप सिंह पोटाई
- राजनांदगांव से भाजपा प्रत्याशी रमन सिंह के सामने कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन
- कवर्धा से भाजपा प्रत्याशी विजय शर्मा के सामने कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर
- दंतेवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी चेतराम अरामी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी छविंद्र महेंद्र कर्मा
- कोंटा से भाजपा प्रत्याशी सोयम मुका के सामने कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा
- चित्रकोट से भाजपा प्रत्याशी विनायक गोयल के सामने कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज
- केशकाल से भाजपा प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम के सामने कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम

प्रशांत अग्रवाल को पुलिस अधीक्षक पद से हटाने भाजपा ने सौंपा चुनाव आयोग को ज्ञापन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल एवं रायपुर जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल की महादेवा बेटिंग (सट्टेबाजी) एप के संगठित अपराध में संलिप्तता उजागर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, चुनाव आयोग संपर्क समिति के डा. विजय शंकर मिश्रा व रायपुर सांसद सुनील सोनी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से मिलकर प्रशांत अग्रवाल को चुनाव के दौरान पुलिस अधीक्षक रायपुर के पद से हटाने की मांग की।

शिकायत पत्र में भाजपा पदाधिकारियों ने चुनाव आयोग को बताया कि 05 नवंबर 2023 को वेब न्यूज़ पोर्टल डेली हंट में शुभम सोनी नमक व्यक्ति की खबर प्रसारित हुई जिसके अनुसार सुभम सोनी के द्वारा स्वयं को महादेवा बेटिंग एप का मालिक बताते हुए छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता श्री भूपेश बघेल को उक्त एप के संचालन का नियंत्रण रायपुर पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल के माध्यम से किया जाना तथा कई बार हफ्ते / प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी धन राशि वसूल करने कि बात एक वायरल वीडियो के द्वारा उजागर की गयी है।

उल्लेखनीय है कि महादेवा एप एक अवैध बेटिंग (सट्टेबाजी) का एप है जिसका संचालन पहले भिलाई छत्तीसगढ़ से तथा बाद में दुबई से भारत में किया जा रहा था । इस एप के जरिये आप जनता से उसकी परिश्रम कि कमाई लूटकर व्यापक मात्रा में धन कि हेरा-फेरी हो रही थी। महादेवा एप के प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा पूर्व से एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। उपरोक्त खबर के अनुसार वर्तमान मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता श्री भूपेश बघेल एवं रायपुर जिला पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल इस संगठित अपराध में सीधे सम्बंधित पाए गए हैं। उक्त घटना यह स्पष्ट करती है कि उनकी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उपरोक्त प्रकृति के सम्बंध रहे हैं इस स्थिति में रायपुर पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा चुनाव में निष्पक्ष कार्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। पूर्व में भी श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा चुनाव कार्य में पक्षपात पूर्ण कार्य करने की शिकायतें कि गयी थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से प्रशांत अग्रवाल को रायपुर जिला पुलिस अधीक्षक से त्वरित रूप से हटाये जाने की मांग की।

छत्तीसगढ़ में अब तो शराबबंदी का चुनावी शिगूफा भी नहीं : शर्मा

रायपुर। शराब के दुष्परिणामो को प्रत्यक्ष देख व भोग छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग को ले मुखर जनमानस को राज्य में सत्तारूढ़ व प्रमुख विपक्षी दल ने ठेंगा दिखा दिया है। चुनाव के समय शराबबंदी का राग अलापने वाले दोनों दलों ने इस विधानसभा चुनाव में तो शराबबंदी का चुनावी शिगूफा से भी तौबा कर लिया है। शराब विरोधी मुहिम में सक्रिय किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने यह बात कहते हुये तंज कसा है कि हर मुख्यमंत्री नितीश कुमार नहीं हो सकता। उन्होंने आशंका जताई है कि लोकलुभावन चुनावी वादे करने वाले करने वाले दल सत्तासीन होने पर अपने वादों को अमल में लाने के लिये आर्थिक संसाधन जुटाने गांव - गांव में और अधिक शराब बिकवायेगी और इसका दुष्परिणाम अंततः आम ग्रामीणों को ही भुगतना पड़ेगा।

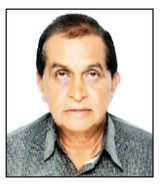

शर्मा ने विज्ञप्ति में जानकारी दी है कि शराब की वजह से आज आमजन त्रस्त हो चले हैं। शासन की नीति के चलते आज शराबभट्ठी जाने वाला हर पियक्कड़ कोचिया बन बैठा है जिसके चलते ग्रामों ?का?? माहौल अशांत हो चला है। मारपीट, लड़ाई - झगड़ा व गाली गलौज आम बात हो गयी है और खासकर शाम ढले तो सभ्य नागरिकों , महिलाओं व नौनिहालों का राह चलना दूभर हो चला है। पूर्व में सत्तारूढ़ रहे भाजपा जहां चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी का वादा करने के बाद भी पूर्ण शराबबंदी करने में नाकाम रही वहीं वर्तमान में सत्तारूढ़ कांग्रेस तो शराबबंदी का वादा कर भी पलटी मार गयी। शराब की वजह से बर्बाद हो रहे घर - परिवार , दिनों-दिन बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं व व्याप्त हो रहे अशांति की कीमत पर शराब पीकर मरने वालों की? चिंता को ले शराबबंदी न करने के? हिमायतियों के रूख से आमजनों को महसूस हो रहा है कि इसके आड़ में शराबबंदी न??? करने के ?पीछे कुछ और ही निहित स्वार्थ है क्योंकि आमजनों को ऐसे ?पियक्कडो से कोई सहानुभूति नहीं है जैसा कि इन्हें है। श्री शर्मा ने आगे कहा है कि गांधी जी के नाम का माला जपने वाले कांग्रेस व रामराज्य का नारा लगाने वाली भाजपा का इस चुनाव में शराबबंदी का चुनावी शिगूफा भी न छोडना न केवल आश्चर्यजनक है वरन् भविष्य के लिये आमजनों को अप्रिय स्थिति के लिये आगाह भी कर रहा है। बिहार में शराबबंदी का चुनावी वादा कर उसे पूरा करने व लगातार झंझावतों के बाद भी अपने सरकार की कीमत पर भी न डिगने वाले मुख्यमंत्री नितीश कुमार को साधुवाद देते हुये उन्होंने कहा है कि हर मुख्यमंत्री नितीश कुमार नहीं हो सकता।

महादेव ऐप का मैनेजर अब खुद को बता रहा मालिक, ये भाजपा और ईडी की है साजिश : बघेल

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा एप और उसके कथित मालिक शुभम सोनी का वीडियो जारी होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के वीडियो को लेकर कहा कि अब ये समझने की जरुरत नहीं है कि ये वीडियो क्यों और कैसे सामने आया है। चुनाव के समय ऐसा बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही जारी किया गया है। यह भी हर कोई समझ रहा है कि ईडी को हथियार बनाकर ही ऐसा किया जा रहा है। बीजेपी अब ईडी के सहारे ही चुनाव लड़ रही है ।मुझे बदनाम करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहली बात तो ये कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। ना मैं कभी इससे उस तरह मिला हूं, जैसा कि

वह दावा कर रहा है। वह किसी सभा समारोह का हिस्सा रहा हो तो मैं नहीं कह सकता ।सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने 4 हजार से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज करवाएं। महादेव एप के प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर हैं ।जो छत्तीसगढ़ का बच्चा-बच्चा जानता है ।लेकिन ये नया मालिक अचानक आ गया ।जो रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर को अपना कर्मचारी बता रहा है।

मैंने ऐसा पहली बार देखा है जब एक मालिक अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हो ।ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ ।इसके बाद जब वीडियो जारी किया गया तो उसमें शुभम सोनी कई बार अपनी बातों को तोड़ मरोड़कर पेश कर रहा है ।इसका मतलब ये है कि वीडियो के साथ छेड़खानी की गई है ।ये वीडियो साजिश के तहत जारी किया गया है ।पिछली बार तो जनता ने 15 सीटों में सिमटाया था ।इस बात उतनी भी नहीं मिलेंगी।

भूपेश बघेल ने कहा दूसरी बात ये है कि यह व्यक्ति दावा कर रहा है कि वह महादेव ऐप का मालिक है ।आश्चर्य की बात है कि यह बात महीनों से इस मामले की जांच कर रही एजेंसी ईडी को भी अभी तक पता नहीं थी। दो दिन पहले तक उसे मैनेजर बता रही थी। छत्तीसगढ़ की जनता सब जान-समझ रही है। वो बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी ईडी को इसका करारा जवाब देगी। आपको बता दें कि महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में बीते दिन एक वीडियो सामने आया था।

सिर्फ चेहरा हैं गिरीश, हॉट सीट राजनांदगांव पर लड़ाई रमन सिंह बनाम भूपेश बघेल

रायपुर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सबसे हॉट सीट राजनांदगांव के मतदाताओं की नजर में यहां लड़ाई रमन बनाम भूपेश है। कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन सिर्फ चेहरा भर हैं। लगातार तीन बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे डॉ. रमन सिंह छह विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। एक बार सांसद चुने गए और केंद्रीय मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सहपाठी और राजनीतिक सहयोगी गिरीश छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के चेयरमैन हैं। ये पहली बार चुनाव मैदान में हैं।

क्षेत्र का चुनावी माहौल भांपने के लिए हम सबसे पहले पुराने बसअड्डे पर स्थित दुकान पर पहुंचे। यहां मिले व्यापारी राजेश महोबिया, महेंद्र कुमार और उनके साथी सारंग। बसअड्डे पर हो रहे निर्माण कार्य को देखकर हमने सवाल किया, इस सरकार में अच्छा काम हो रहा है। छूटते ही राजेश बोले, पांच साल कुछ नहीं हुआ। 2018 में किए वादे भी कांग्रेस ने नहीं पूरे किए। डॉ. रमन के केंद्रीय मंत्री

रहते घाटे के चलते बंद की गई कॉटन मिल को शुरू कराने का वादा भूपेश बघेल ने ही किया था। कुछ नहीं हुआ।

भारतमाता चौक स्थित सराफा दुकान के संचालक स्वरूप जैन का मानना है कि कांग्रेस रेवड़ियां बांटकर जीतना चाहती है। किसानों के लिए रियायतों की घोषणा कर रही है। लेकिन, शराबबंदी के वादे से मुकर गई। शराबखोरी सबसे बड़ी समस्या है। इससे ग्रामीणों का जीवन नष्ट हो रहा है। साजा और कवर्धा की सांप्रदायिक हिंसा का असर पूछने पर उनका कहना था, वादाखिलाफी और विकास की जो बात करेगा, जनता उसी के साथ जाएगी।

राजनांदगांव में कांग्रेस ने पांच स्थानीय नेताओं की दावेदारी खारिज करते हुए रायपुर के रहने वाले गिरीश पर भरोसा जताया है। इससे स्थानीय दावेदारों के साथ कई पदाधिकारी असंतुष्ट हैं। स्थानीय बनाम बाहरी के इस मुद्दे को भाजपाई भी हवा दे रहे हैं। हालांकि, गिरीश राजनांदगांव में ननिहाल होने की दुहाई दे रहे हैं।

बरकापारा में ऑटो पार्ट्स की दुकान के संचालक बबलू अहमद निराशा भरे भाव से कहते हैं, सरकार किसी की हो, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। सरकार गांवों के लिए तमाम रियायतें देकर व्यापारी वर्ग पर टैक्स का बोझ बढ़ा देती है। कहा कि यह तो सभी जानते हैं, हमारा वोट कहां जाता है। यहां मिले युवा मोहम्मद अफर का कहना था, विकास और रोजगार के मुद्दे पर कोरे आश्वासन ही हैं।2018 में रमन ने अटल की भतीजी को हराया था = 2018 में डॉ. रमन सिंह ने कांग्रेस की प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को 16933 हजार मतों से हराया था।

विकास में पहले जैसी तेजी नहीं = महेंद्र बोले, डॉक्टर साहब के आगे कोई नहीं। गिरीश महज चेहरा हैं। उनके पीछे मुख्यमंत्री बघेल हैं। समझिए वही चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा राज में विकास बहुत हुआ। अब भी काम हो रहा है, लेकिन भाजपा राज जैसी तेजी नहीं है।

रमन सिंह, भाजपा- 1999 में सांसद, केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग राज्यमंत्री बने। 2003 से 2018 तक तीन बार सीएम। अब भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

गिरीश देवांगन, कांग्रेस- छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के चेयरमैन हैं। सीएम भूपेश बघेल के सहपाठी व सियासी सहयोगी। पहली बार चुनाव में मैदान में।

पहले चरण में दांव पर 223 उम्मीदवारों की किस्मत, 20 सीटों का समीकरण, किसका पलड़ा भारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संभाग बस्तर है, जहां से कुल 90 सीटों में से 12 सीटें आती हैं। आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में कुल सात जिले आते हैं। सात जिलों के संभाग में यहां छत्तीसगढ़ की 12 विधानसभा और एक लोकसभा सीट है। बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों में 11 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) और एक सीट सामान्य है। इनमें बस्तर, कांकेर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर की सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। वहीं जगदलपुर विधानसभा सीट सामान्य है। वर्तमान में 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है।

वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहीं से करारी हार का सामना करना पड़ा था और सत्ता गंवानी पड़ी थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से बस्तर संभाग काफी अहम माना जाता है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर संभाग से खुलती है। इसलिए माना जाता है कि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है, तो बस्तर किला पर फतह हासिल करना बहुत जरूरी है। प्रदेश में कुल 90 विधानसभा सीट हैं, जिनमें 39 सीटें आरक्षित हैं। 39 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं । 29 में से 12 सीटें बस्तर संभाग से आती हैं। 15 साल तक सत्ता पर काबिज रही बीजेपी को साल 2018 में यही से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, इसलिए बीजेपी में सत्ता पाने की बैचेनी है। बस्तर में पीएम मोदी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, जेपी नड्डा, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओपी माथुर समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता दौरा कर चुके हैं। बस्तर संभाग के रहवासियों की मुख्य आय का स्त्रोत वनोपज और खेती-किसानी है।

बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटों का सियासी समीकरण-

बस्तर- इस सीट से इस बार बीजेपी प्रत्याशी मनीराम कश्यप के सामने कांग्रेस प्रत्याशी लखेश्वर बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। वह दो बार के विधायक रह चुके हैं। वह साल 2018 का चुनाव काफी बड़े अंतर से जीते थे। वहीं मनीराम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो तीन बार जिला पंचायत सदस्य और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। यहां कुल मतदाता 167635 हैं। इसमें पुरुष 81184 और महिला 86449 हैं। वहीं ट्रांसजेंडर 2 हैं।

जगदलपुर- इस सीट से इस बार से बीजेपी प्रत्याशी किरणदेव सिंह के सामने कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। दोनों नगर निगम में पूर्व महापौर रह चुके हैं। किरण सिंहदेव की पहली बार चुनावी मैदान में हैं। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 205953 है। इनमें पुरुष 98778, महिला 107144 और ट्रांसजेंडर मतदाता 31 हैं।

नारायणपुर- इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप के सामने कांग्रेस प्रत्याशी चंदन कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। केदार कश्यप दो बार विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में भाजपा के महामंत्री हैं। वहीं चंदन कश्यप पहली बार के विधायक हैं। उन्होंने 2018 में केदार को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 190672 है। इनमें पुरुष 92030, महिला 98639 और ट्रांसजेंडर मतदाता 3 हैं।

कांकेर- इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी आशाराम नेताम के सामने कांग्रेस प्रत्याशी शंकर ध्रुव चुनाव लड़ रहे हैं। नेताम पहली बार चुनाव मैदान में है। वे ग्रामीण मंडल मंत्री हैं। वहीं शंकर ध्रुव ग्राम पंचायत मुड़पार के सरपंच रह चुके हैं। पहली बार 2013 में विधायक बने। यहां कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर दिख रही है। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 87161 है। इनमें पुरुष 87161, महिला 95082 और ट्रांसजेंडर मतदाता 2 हैं।

कोंडागांव- इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी लता उसेंडी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2003 से भाजपा की लता उसेंडी विधायक बनीं। 2008 में भी वो दोबारा जीतीं। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मोहन मरकाम ने लता को हराकर विधायकी पर कब्जा कर लिया। 2018 में भी वे दोबारा जीतकर आए। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 188520 हैं। इनमें पुरुष 91044, महिला 97473 और ट्रांसजेंडर मतदाता 3 हैं।

केशकाल- इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम के सामने कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व आईएएस ऑफिसर टेकाम पहली बार चुनाव मैदान में हैं। इस सीट से नए चेहरे हैं। वहीं संतराम नेताम 2013 में विधायक बने। 17 साल तक पुलिस विभाग में सेवाएं दे चुके हैं। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 206304 है। इनमें पुरुष 100230, महिला 106070 और ट्रांसजेंडर मतदाता 4 हैं। क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है।

दंतेवाड़ा- इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी चेतराम अटामी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी छविंद्र महेंद्र कर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। अटामी 2015 से 2020 तक जिला पंचायत सदस्य रहे। दंतेवाड़ा सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा की परंपरागत सीट रही है। वर्तमान में दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस से देवती कर्मा विधायक हैं। देवती कर्मा बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की पत्नी हैं, जिन्हें नक्सलियों ने झीरम घाटी मे गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस बार कांग्रेस ने देवती कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा को टिकट दिया है। इस सीट पर हुए पिछले 4 विधानसभा चुनावों में तीन बार कांग्रेस की जीत हुई, जबकि एक बार बीजेपी की जीत हुई है। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 192323 है। इनमें पुरुष 90084, महिला 102237 और ट्रांसजेंडर मतदाता 2 हैं।

अंतागढ़- इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी विक्रम उसेंडी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी रुप सिंह पोटाई चुनाव लड़ रहे हैं। उसेंडी पूर्व सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। रमन सरकार में 2008 में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वहीं पोटाई सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष और आदिवासी कमेटी जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 175965 है। इनमें पुरुष 88512, महिला 87445 और ट्रांसजेंडर मतदाता 8 हैं।

भानुप्रतापपुर- इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी गौतम उईके के सामने कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी चुनाव लड़ रहे हैं। उईके पहली बार चुनाव मैदान में हैं। वे 2000 से 2015 तक जनपद सदस्य रह चुके हैं। वहीं सावित्री मंडावी पूर्व विधायक मनोज मंडावी की पत्नी हैं। वो उपचुनाव में जीत हासिल की थीं। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 201826 है। इनमें पुरुष 98549, महिला 104275 और ट्रांसजेंडर मतदाता 2 हैं।

कोंटा- इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी सोयम मुका के सामने कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से वर्तमान मंत्री और विधायक कवासी लखमा के नाम पांच बार विधायक बनने का रिकार्ड है। वो छठवीं बार चुनाव मैदान में हैं। बस्तर चार बार विधायक बनने वालों में कांग्रेस के झितरूराम बघेल का नाम आता है। उन्हें छोड़ दिया जाए तो अन्य कोई भी दल प्रत्याशी तीन बार से अधिक चुनाव नहीं जीत सका है। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 190672 है। इनमें पुरुष 92030, महिला 98639 और ट्रांसजेंडर मतदाता 3 हैं।

क्या इस सट्टे ने लगा दिया बघेल सरकार की साख पर बट्टा?

अभिनय आकाश

छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले राउंड की वोटिंग होनी है। लेकिन पहले राउंड की वोटिंग से पहले ही महादेव बैटिंग एप को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है जो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की परेशानियां और बढ़ा सकती है। भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। तो वहीं, बघेल अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है महादेव बेटिंग ऐप, कैसे काम करता है ये एप और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार क्यों कटघरे में है। छत्तीसगढ़ का एक शहर है भिलाई, इतिहास में इस जगह को स्टील प्लांट वाले शहर के रूप में जाना जाता था। करीब 10 साल पहले इसी शहर के नेहरू नगर इलाके में एक जूस की दुकान होती थी। जूस की दुकान का नाम महादेव जूस कॉर्नर और इसे चलाने वाले का नाम सौरभ चंद्रा था। इसी जूस की दुकान से कुछ ही दूरी पर एक टॉयर की दुकान भी हुआ करती थी। इस दुकान के मालिक का नाम रवि उप्पल था। दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों का ही धंधा समय के साथ चल रहा था। लेकिन दोनों को ही सट्टे की लत लग गई। ऑनलाइ सट्टेबाजी के लिए उन्होंने प्ले स्टोर में मिलने वाली सट्टेबाजी एप्स का सहारा लिया। शुरुआत छोटे सट्टे से हुई। फिर ये सट्टे में लगाए जाने वाले पैसे की तादाद बढ़ती गई। लेकिन फिर दोनों को इसमें होने लगा नुकसान। दोनों पैसा लगाते रहे और गंवाते रहे। देखते ही देखते सौरभ 15 लाख और रवि 10 लाख रुपए गंवा चुका था। वो पैसे डुबाते गए लेकिन एप्स को पैसे नहीं चुका रहे थे। लिहाजा कर्ज में उतरने लगे। दोनों को फिर देश छोड़कर भागने का ही रास्ता सूझा। दोनों ने दुबई का टिकट कटा लिया। दुबई में पहुंचने के बाद दोनों के पास कमाने का संकट था। दोनों ही मुलाकात दुबई में एक पाकिस्तानी से हुई। फिर सौरभ, रवि ने शेख के सामने ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लान शुरू किया। कोरोना लॉकडाउन के बाद दोनों ने एक एप बनवाई जिसका नाम महादेव बुक रखा। महादेव बुक का काम लोगों से अलग अलग गेम्स में सट्टा लगवाना था। इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलते थे। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए इस ऐप का जाल तेजी से फैला और सबसे ज्यादाखाते छत्तीसगढ़ में खुले। इस ऐप से धोखाधड़ी के लिए एक पूरा खाका बनाया गया था। यूजर को केवल शुरुआत में फायदा और बाद में नुकसान होता था। फायदे का 80 त्न हिस्सा दोनों अपने पास रखते थे। सट्टेबाजी ऐप रैकेट एक ऐसी मशीन की तरह काम करता है, जिसमें एल्गोरिदम ये तय करता है कि ऐप में अपना पैसा लगाने वाले केवल 30 ग्राहक ही जीतें। हिदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ये पूरा खेल इतना बड़ा है कि दुबई के प्रमोटरों के पास पूरे इंडिया में 4 हजार से ज्यादा पैनल हैं और हरेक पैनल के पास 200 से ज्यादा उसके काम करने वाले हैं। यानी स्कीम में पैसा लगाने वाले 8 लाख से ज्यादा लोग हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामला तब से सुर्खियों में आया, जब ईडी ने दावा किया कि उसने एक कैश कूरियर के ईमेल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है। जिसमें खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूएई में स्थित ऐप प्रमोटरों से कथित तौरप र 508 करोड़ रुपये लिए थे। वहीं महादेव बुक का मालिक अब हिरासत में है। उसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर महादेव ऐप समेत 22 अवैध सट्टेबाजी प्लैटफॉर्म्स के खिलाफ ब्लॉक आदेश जारी किए हैं। आई राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा करने का अधिकार होने के बावजूद इन प्लैटफॉर्म्स को ब्लॉक करने के लिए कोई अनुरोध नहीं भेजा। छत्तीसगढ़ सरकार के पास वेबसाइट / ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया जबकि वे पिछले 1.5 वर्षों से इसकी जांच कर रहे हैं। पहला और एकमात्र अनुरोध ईडी की तरफ से मिला है और उस पर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को इसी तरह का अनुरोध करने से किसी ने नहीं रोका।

चुनावों में कांग्रेस खो रही अपनी बढ़त

अजय सेतिया

पांच विधानसभाओं के चुनाव की जब घोषणा हुई थी, तब ऐसा लग रहा था कि मिजोरम को छोड़कर बाकी चारों राज्यों में कांग्रेस का पलड़ा काफी भारी रहेगा। जैसे 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा को कर्नाटक और तीनों हिन्दी भाषी राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था, ठीक वैसे ही इस बार होगा। चुनावी आकलन इस तरह के भी आ रहे थे कि तीनों हिन्दी भाषी राज्य तो कांग्रेस जीतेगी ही, तेलंगाना में भी कांग्रेस जीत सकती है। हालांकि कुछ महीने पहले तक तेलंगाना में जो भाजपा सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति को कड़ा मुकाबला देती दिखाई दे रही थी, वह चुनाव आते आते मुकाबले से बाहर हो गई, क्योंकि उसने पिछड़ी जातियों के उभरते हुए नेता बंडी संजय को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा कर तेलंगाना में बहुत कम प्रभाव रखने वाली रेड्डी जाति के किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तेलंगाना में चर्चा तो यहां तक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य की राजनीति को देखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) के लिए मैदान खाली करने का काम किया है।

बंडी संजय के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद से हटते ही कांग्रेस मुख्य मुकाबले में आ गई और ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि कड़े मुकाबले में केसीआर का पलड़ा भारी है। भारतीय जनता पार्टी की अगर तेलंगाना में बड़ी भूमिका की उम्मीद नहीं है, तो वह वहां कांग्रेस को हरवाने का काम करेगी, क्योंकि केसीआर भविष्य में संसद में बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस की तरह मोदी के लिए संकट के साथी बनेंगे। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी स्थितियों में काफी परिवर्तन आ गया है। ऐसा लगने लगा है कि कर्नाटक से बहने लगी कांग्रेस की हवा पांच राज्यों के चुनाव नतीजों में थम जाएगी, जिसके बूते कांग्रेस 2024 जीतने का सपना देख रही है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव । नवंबर को हैं। पहले चरण के चुनावों से सिर्फ पांच दिन पहले महादेव एप का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ संबंध होने का खुलासा होने के बाद भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है।

महादेव बेटिंग एप ऑनलाइन सट्टेबाजी का एप है, जिसके मेन प्रमोटर छत्तीसगढ़ के सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल हैं। ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में दावा किया कि महादेव एप प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

ईडी ने कहा कि 5.39 करोड़ रुपये के साथ गिरफ्तार किए गए असीम दास ने पूछताछ में मुख्यमंत्री को पैसा दिए जाने की बात कही है। एप चलाने वाले दुबई में जाकर बस चुके हैं, एप के भारत में वांछित मालिक शुभम सोनी ने दुबई से ऑन कैमरा दावा किया है कि उन्हें बघेल सरकार ने संरक्षण दिया था, जिसके बदले वह मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहाकार और बीबीसी के पूर्व पत्रकार विनोद वर्मा को दस लाख रूपए महीना पहुंचा रहे थे। विनोद वर्मा मुख्यमंत्री बघेल का करीबी रिश्तेदार है।

यह घोटाला खुलने के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। महादेव एप घोटाला खुलने से ठीक पहले हुए ओपिनियन पोल में कांग्रेस और भाजपा की कांटेदार टक्कर में कांग्रेस की थोड़ी बढ़त दिखाई गई थी। एप घोटाला खुलने के बाद स्थितियां भाजपा के अनुकूल होती जा रही हैं। भाजपा रेस में बराबरी पर आ गई है।

मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को वोट पड़ेंगे। वहां कभी अर्जुन सिंह की तूती बोलती थी। अर्जुन सिंह के तीन चेले थे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और अजीत जोगी। बाद ये तीनों भी मुख्यमंत्री बने, दिग्विजय सिंह 1993 से 2003 तक दस साल के लिए मध्यप्रदेश में, अजीत जोगी मध्यप्रदेश बंटवारे के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। बाद में कांग्रेस से अलग हो कर जनता कांग्रेस बनाई। जोगी की जनता कांग्रेस की वजह से कांग्रेस 15 साल तक छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर रही, उनके देहांत के बाद उनका बेटा अमित जोगी उस पार्टी को चला रहा है और इस समय भी चुनाव में कांग्रेस के सामने ताल ठोक रहा है।

अर्जुन सिंह के तीसरे चेले कमलनाथ 2018 में एक साल के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वह एक साल ही मुख्यमंत्री रह पाए क्योंकि ग्वालियर राजघराने के वारिस ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत करके उनकी सरकार गिरा दी। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनवाने में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अहम भूमिका थी। दिग्विजय सिंह राघोगढ़ के राजा बलभद्र सिंह के बेटे हैं, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर राज घराने के वारिस हैं। ग्वालियर और राघोगढ़ राजघरानों में पुरानी दुश्मनी के चलते दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। अब वही दिग्विजय सिंह कमलनाथ के रास्ते का काँटा बन रहे हैं।

अगर सोनिया और राहुल उन्हें मुख्यमंत्री बनवाने को तैयार होते तो दिग्विजय सिंह चुनाव जीतने के लिए जान की बाजी लगा देते। जब चुनाव शुरू हुआ था, तो लगता था कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस जीत रही है। लेकिन टिकटों की मारामारी में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की खुली भिडंत हो गई। दोनों खेमे एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। बल्कि कमलनाथ ने तो कांग्रेस वर्करों को खुल्लम खुल्ला कह दिया कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, वही टिकटों में गड़बड़झाला करवा रहे हैं।

कांग्रेस में यह पुराना इतिहास भी रहा है। डी.पी. मिश्रा ने श्यामा चरण शुक्ला को सीएम बनवाया था। बाद में डी.पी.मिश्रा ने ही उनके पाँव खींचे और मुख्यमंत्री पद से हटवा दिया। अब वही काम दिग्विजय सिंह कमलनाथ के साथ कर रहे हैं। कांग्रेस की इस आपसी सिर फुटौवल ने भाजपा का रास्ता आसान कर दिया है। रही सही कसर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरी कर रहे हैं, जिन्हें समझौते में छह सीटें न देकर कांग्रेस ने उन्हें अपना दुश्मन बना लिया है। उन्होंने बड़ी तादाद में अपने उम्मीदवार खड़े करके कांग्रेस के खिलाफ धुंआधार प्रचार शुरू कर दिया है। वह कांग्रेस को चालू और धोखेबाज पार्टी बता रहे हैं, जबकि कमलनाथ सरकार उनके एक विधायक के समर्थन से ही बनी थी। भाजपा ने मध्यप्रदेश में दो केन्द्रीय मंत्रियों सहित सात सांसदों को टिकट देकर मुख्यमंत्री के संबंध में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कहने लगे थे कि वह मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, कह नहीं सकते। अगर कांग्रेस पार्टी होती तो शिवराज सिंह चौहान औपचारिकता के लिए ही चुनाव प्रचार करते, लेकिन वह इतना धुंआधार प्रचार कर रहे हैं कि सत्ता आने पर मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं। एक ताज़ा ओपिनियन पोल में कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है।

पोल्स्टर्स इंडिया के ओपिनियन पोल के हिसाब से महिला वोटरों के बीच भाजपा कांग्रेस से 20 प्रतिशत आगे है, इसी तरह ओबीसी और जनजातीय समाज के बीच भी भाजपा आगे दिख रही है। इसकी वजह है शिवराज सिंह चौहान का ओबीसी होना और कमलनाथ का बनिया होना। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक़ कांग्रेस पर भाजपा की बढ़त 5 प्रतिशत है। इतनी बढ़त रहने पर भाजपा की सीटें कांग्रेस से 25-30 तक ज्यादा हो सकती हैं।

राजस्थान में भी स्थितियां पूरी तरह बदली हुई दिखाई दे रही हैं। भाजपा में मसला वसुंधरा राजे बनाम आलाकमान बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में असमंजस की स्थिति को खत्म करना शुरू कर दिया है। भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के तीन सांसद दावेदारों को विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया है। केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल के अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं।

चुनाव शुरू हुए थे तो गजेन्द्र सिंह और अर्जुन मेघवाल इस तरह व्यवहार कर रहे थे, जैसे भाजपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार वहीं हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद भाजपा आलाकमान अपनी मर्जी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उपचुनाव का सहारा भी ले सकता है। लेकिन इन तीनों दावेदारों में से कोई भी ओबीसी नहीं है। भाजपा आलाकमान अगर वसुंधरा राजे की जगह किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाना भी चाहेगा, तो उसकी चॉइस किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाने की होगी। अब यह भी साफ़ हो गया है कि भाजपा ने जातिगत वोट बैंक को साधने और उनके आसपास की सीटों पर भी उनके प्रभाव का फायदा लेने के लिए सांसदों को मैदान में उतारा है।

भाजपा का फोकस ओबीसी वोटों पर है, जो राजस्थान में प्रभावशाली राजपूत और जाटों से ज्यादा महत्व रखते हैं। वसुंधरा राजे ने अपनी स्थिति यह कह कर साफ़ कर दी है कि वह रिटायर होने को तैयार हैं, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया है कि वह राजस्थान छोड़ कर नहीं जाएँगी। यानी वह मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी से खुद को बाहर नहीं मानती हैं। लगता है कि भाजपा ने किसी को भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाने, लेकिन वसुंधरा राजे को फिर से महत्व देकर सही रणनीति अपनाई है। भाजपा ने क़ानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेर लिया है। इन दोनों ही मुद्दों पर सचिन पायलट अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सिमट कर रह गए हैं और चुनाव जिताने की सारी जिम्मेदारी अशोक गहलोत पर आ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर ईडी के शिकंजे ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। ताज़ा ओपिनियन पोल में भी भाजपा की आसान जीत की भविष्यवाणी की गई है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-34)

गतांक से आगे...

मुक्त और शान्त वही है, जो हृदय से सभी वासनाओं को छोड़ देता है, वही परमेश्वर है। वह दसों दिशाओं में घूमते हुए भ्रान्तिवश द्रष्टव्य पदार्थों को देखने में सक्षम है। प्रयत्नपूर्वक आचरणशील ज्ञानी पुरुषों के लिए यह संसार गोष्पद (गाय का खुर) की तरह सहज ही पार उतरने योग्य बन जाता है। शरीर के बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे तथा सभी दिशाओं में सर्वत्र आत्मा ही विद्यमान है, उसके निमित्त यह संसार अनात्ममय नहीं होता।

हे निष्पाप! यह और है मैं अन्य हूँ, इस प्रकार की भ्रान्त धारणा का परित्याग कर दे। ऐसा कोई स्थल नहीं, जहाँ मेरा अस्तित्व नहीं, उस वस्तु का अभाव है, जो आत्मरूप न हो। मैं ऐसी कौन सी वस्तु की कामना करूँ ? सब में सत् और चिन्मय तत्त्व संव्याप्त है। यह सब कुछ ब्रह्ममय ही है, सबमें आत्मा का ही विस्तार है। सर्वव्यापी और नित्य सच्चिदानन्द घन ब्रह्म में काल्पनिक भावों की सम्भावना नहीं है। यह तत्त्व शोक, मोह, जरा और जन्म से रहित है।

आत्मतत्त्व में जो विद्यमान है, वही सब कुछ है। अतएव हमेशा सभी जगह किसी पदार्थ की अभिलाषा न करते हुए सहज में जो उपलब्ध हो, उसी का आसक्तिरहित होकर उपभोग करते हुए शोकरहित होकर रहना चाहिए। किसी वस्तु का न तो परित्याग और न ग्रहण- इस प्रकार सन्तापहीन होकर रहना चाहिए। हे महामते ! जिस व्यक्ति का यह जन्म आखिरी है (अर्थात् आगे जिसका जन्म नहीं होना है), उसमें शीघ्र ही श्रेष्ठ प्रजाति की मुक्ता के समान निर्मल विद्या प्रविष्ट होती है। जिनके मन में वैराग्य भाव है, ऐसे ज्ञानियों द्वारा अपने अनुभवजन्य ज्ञान से यह अभिव्यक्त किया गया है कि द्रष्टा को दृश्य के माध्यम से जो निश्चयात्मिका सुखानुभूति होती है, वह आत्मतत्त्व से प्रकट हुआ स्पन्दन है, जिसकी हम उत्तम रीति से उपासना करते हैं। वासनात्मक चिन्तन के साथ द्रष्टा, दृश्य और दर्शन इन तीनों का परित्याग करके प्रकाशमान आत्मा के हम उपासक हैं। अस्ति नास्ति के बीच विद्यमान प्रकाशों के भी प्रकाशक सनातन आत्मा के हम उपासक हैं। हमारे हृदय में वह आत्मतत्त्व महेश्वर के रूप में विद्यमान हैं। जो पुरुष इस आत्मा को त्यागकर अन्य वस्तु की प्राप्ति हेतु यत्नशील हैं, वे अपने हाथ में स्थित कौस्तुभमणि को छोड़कर अन्य रत्न की अभिलाषा करते हैं। इन्द्र द्वारा वज्र से पर्वतों को तहस-नहस करने की तरह इन्द्रियरूपी शत्रु चाहे बलवान् हों या कमजोर, उन्हें विवेकरूपी दण्डप्रहार से बारम्बार प्रताड़ित करना चाहिए।

विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे सीवी रमन

सुधांशु

सीवी रमन का जन्म 7 नवम्बर सन 1888 ई. में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था। सीवी रमन के पिता चन्द्रशेखर अय्यर एसपीजी कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक थे। सर सीवी रमन की माता पार्वती अम्मल एक सुसंस्कृत परिवार की महिला थीं। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा विशाखापत्तनम में ही हुई। सर चन्द्रशेखर वेंकटरामन ने बारह वर्ष की अल्पावस्था में ही मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी।

कई दशक पहले की गई कोई वैज्ञानिक खोज, जिसे वर्षों पहले नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया हो और आज भी वह खोज उतनी ही प्रासंगिक हो तो उससे जुड़े वैज्ञानिकों को बार-बार याद करना जरूरी हो जाता है। चन्द्रशेखर वेंकटरमन या सर सीवी रमन एक ऐसे ही प्रख्यात भारतीय भौतिक-विज्ञानी थे, जिन्हें उनके जन्मदिन के मौके पर दुनिया भर में याद किया जा रहा है। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहला एशियाई होने का गौरव प्राप्त है।

प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका आविष्कार उनके नाम पर ही रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रमन प्रभाव का उपयोग आज भी विविध वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। भारत से अंतरिक्ष मिशन चन्द्रयान ने चांद पर पानी होने की घोषणा की तो

इसके पीछे भी रमन स्पैक्ट्रोस्कोपी का ही कमाल था।

फोरेंसिक साइंस में तो रमन प्रभाव का खासा उपयोग हो रहा है और यह पता लगाना आसान हो गया है कि कौन-सी घटना कब और कैसे हुई थी। दरअसल, जब खास तरंगदैर्ध्य वाली लेजर बीम किसी चीज पर पड़ती है तो ज्यादातर प्रकाश का तरंगदैर्ध्य एक ही होता है। लेकिन हजार में से एक ही तरंगदैर्ध्य मे परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को स्कैनर की मदद से ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। स्कैनर में विभिन्न वस्तुओं के ग्राफ का एक डाटाबेस होता है। हर वस्तु का अपना ग्राफ होता है, हम उसे उन वस्तुओं का फिंगर-प्रिन्ट भी कह सकते हैं। जब स्कैनर किसी वस्तु से लगाया जाता है तो उसका भी ग्राफ बन जाता है। और फिर स्कैनर अपने डाटाबेस से उस ग्राफ की तुलना करता है और पता लगा लेता है कि वस्तु कौन-सी है। हर अणु की अपनी खासियत होती है और इसी वजह से रमन स्पैक्ट्रोस्कोपी से खनिज पदार्थ, कार्बनिक चीजों, जैसे- प्रोटीन, डीएनए और अमीनो एसिड का पता लग सकता है।

सीवी रमन ने जब यह खोज की थी तो उस समय काफी बड़े और पुराने किस्म के यंत्र थे। खुद रामन ने भी रमन प्रभाव की खोज इन्हीं यंत्रों से की थी। आज रमन प्रभाव ने प्रौद्योगिकी को बदल दिया है। अब हर क्षेत्र के वैज्ञानिक रमन प्रभाव के सहारे कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। इसके चलते बैक्टीरिया, रासायनिक प्रदूषण और विस्फोटक चीजों का पता आसानी से चल जाता है। अब तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसे सिलिकॉन पर भी इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया है। ग्लास की अपेक्षा सिलिकॉन पर रमन प्रभाव दस हजार गुना ज्यादा तीव्रता से काम करता है। इससे आर्थिक लाभ तो होता ही है साथ में समय की भी काफी बचत हो सकती है।

कलकत्ता विश्वविद्यालय में वर्ष 1917 में भौतिकी के प्राध्यापक का पद सृजित हुआ तो वहां के कुलपति आशुतोष मुखर्जी ने उसे स्वीकार करने के लिए सीवी रमन को आमंत्रित किया। रमन ने उनका निमंत्रण स्वीकार करके उच्च सरकारी पद से त्याग-पत्र दे दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में सीवी रमन ने कुछ वर्षों में वस्तुओं में प्रकाश के चलने का अध्ययन किया। वर्ष 1921 में रमन विश्वविद्यालयों की कांग्रेस में प्रतिनिधि बनकर ऑक्सफोर्ड गए। सन 1954 में सर सीवी रमन भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया तथा सन 1957 में लेनिन शान्ति पुरस्कार प्रदान किया था। चन्द्रशेखर वेंकटरमन का 82 वर्ष की उम्र में 21 नवम्बर 1970 में बंगलुरु में निधन हुआ था।

ईरान-इजराइल के बीच युद्ध हो गया तो परिणाम क्या होंगे?

नीरज कुमार दुबे

आतंकवादी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंकवादी हमला कर करीबन 1400 लोगों की जान ले ली तो ईरान बेहद खुश हुआ क्योंकि इजराइल में घुस कर हमला करना असंभव माना जाता था। देखा जाये तो दुनियाभर में इजराइल का सुरक्षा तंत्र अभेद्य माना जाता था लेकिन हमास ने उसे भेद कर ईरान को जश्न मनाने का मौका दे दिया था। लेकिन अब जबकि इजराइल की ओर से गाजा पर भीषण हमले हो रहे हैं और गाजा में मरने वालों की संख्या 10 हजार पार कर गयी है तो ईरान सकते में है। ईरान को समझ नहीं आ रहा है कि वह जश्न मनाये या अपने किये पर पश्चाताप करे। ईरान में गाजा के हालात को देखते हुए बैठकों का दौर जारी है लेकिन वर्तमान स्थिति से निबटने का उपाय किसी को नहीं सूझ रहा है। इसीलिए कोरी लफ्फाजी कर माहौल को गर्म रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर उसने गाजा पट्टी पर अपनी निरंतर बमबारी नहीं रोकी तो उसे ''कई मोर्चों'' पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हालांकि इसके साथ ही ईरान इस बात को भी समझ रहा है कि यदि वह सीधे इस युद्ध में उतरा तो उसके लिए भी मुश्किल हालात खड़े हो सकते हैं क्योंकि मौका देखकर अमेरिका भी उस पर हमला करना चाहेगा।

जहां तक ईरान की धमकी की बात है तो माना जा रहा है कि उसने इसके जरिये यह संकेत दिया है कि वह

अपने लिये काम करने वाले मिलिशिया संगठनों को इजराइल पर हमले तेज करने की धमकी दे सकता है। हम आपको बता दें कि लेबनान के साथ लगती इजराइली सीमा पर कम स्तर की झड़पों में शामिल हिजबुल्ला आतंकवादी समूह और सीरिया में असद सरकार दोनों की ईरान के साथ घनिष्ठता है। दूसरी ओर, ईरान की बढ़ती शत्रुतापूर्ण बयानबाजी को देखते हुए, अमेरिका और इजराइल रणनीति बना चुके हैं कि अगर तेहरान संघर्ष में शामिल होता है तो क्या करना है। देखा जाये तो ईरान को लेकर इजराइल की स्थिति किसी प्रकार का समझौता नहीं करने वाली रही है। पहले भी उसने ईरान के परमाणु केंद्रों पर सर्जिकल हमले करने की पैरवी की थी और वह ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या में भी संलिप्त रहा है। ऐसा लग रहा है कि गाजा युद्ध में ईरान का संभावित प्रवेश शत्रुओं के बीच दुश्मनी में एक नया अध्याय शुरू करेगा और युद्ध को सीधे ईरान के दरवाजे तक ले जाएगा।

वैसे तो लगता नहीं है कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा लेकिन सवाल उठता है कि यदि ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो उसके सैन्य और राजनीतिक परिणाम क्या होंगे? यदि यह युद्ध होता है तो एक बात स्पष्ट है कि ईरान को इजराइल की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना होगा। इजराइल के साथ खुलकर संघर्ष ईरान के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। इससे न केवल इजराइली सेना ईरानी केंद्रों को निशाना बना सकती है, बल्कि इसका ईरान की उस सरकार पर राजनीतिक असर भी पड़ सकता है जो तेजी से अपने नागरिकों के बीच ही अलोकप्रिय होती जा रही है।

आग से खेलने को हमेशा आतुर दिखने वाले ईरान की चेतावनियों में कितना दम है इसका अंदाजा उसकी पूर्व की चेतावनियों के हश्र से भी लगाया जा सकता है। हम आपको याद दिला दें कि अमेरिका द्वारा मशहूर युद्ध नायक कासिम सुलेमानी की जनवरी 2020 में हत्या किए जाने के बाद ईरानी प्राधिकारियों ने ''करारा जवाब'' देने का वादा किया था लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत कमजोर रही थी। ईरान ने इराक की दो एयरफील्ड पर पूर्व चेतावनी देते हुए हमला किया था जहां अमेरिकी सैनिक तैनात थे। यही नहीं, सीरिया में रूस और ईरान समर्थित बशर अल-असद सरकार के बने रहने के बावजूद ईरान ने कभी भी इजराइल पर हमला करने की जुर्रत नहीं की जबकि इजराइल ने सीरिया में ईरानी संपत्तियों को लगातार निशाना बनाया है। इजराइल के बारे में ईरान के रुख की बात करें तो आपको बता दें कि वह इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को ही खारिज करता है और इसे देश नहीं, बल्कि एक यहूदी संस्था मानता है। ईरान की आधिकारिक घोषणाएं इजराइल विरोधी बयानों से भरी पड़ी हैं। इसके अलावा इस साल जून में तेहरान ने अपनी नयी मिसाइल का परीक्षण किया था और यह दावा किया था कि इसमें इजराइल तक पहुंचने की क्षमता है। इसके अलावा, ईरानी सैन्य कमांडर हिज़्बुल्लाह और हमास सहित पूरे क्षेत्र में इज़राइल के दुश्मन समूहों को प्रशिक्षण और हथियार देने पर गर्व करते हैं। बहरहाल, अब ईरान को एक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है कि उसे और उसके प्रॉक्सी मिलिशिया को गाजा पर इजरायल के आक्रमण का जवाब कैसे देना चाहिए। ईरान द्वारा प्रशिक्षित और पल्लिवत हमास का जो हश्र इजराइल ने किया है उसको देखते हुए ईरान की आगे बढ़ने की हिम्मत तो नहीं हो रही है लेकिन अगर ईरान कुछ नहीं करता है तो उसके तेजतर्रार नेताओं को अपनी विश्वसनीयता खोने का खतरा भी सता रहा है।

हिन्द स्वराज्य

छुटकारा (भाग-5)

गतांक से आगे...

प्रश्न- सब ऐसा कब करेंगे और कब उसका अन्त आयेगा ?

उत्तर- आप फिर भूलते हैं। सबकी न तो मुझे परवाह है, न आपको होनी चाहिए। आप अपना देख लीजिये, मैं अपना देख लूँगा- -यह स्वार्थ- वचन माना जाता है, लेकिन यह परमार्थ वचन भी है। मैं अपना उजालूँगा- अपना भला करूँगा, तभी दूसरे का भला कर सकूँगा। अपना कर्तव्य मैं कर लूँ, इसी में काम की सारी सिद्धियाँ समायी हुई हैं। आपको विदा करने से पहले फिर एक बार मैं यह दोहराने की इजाजत चाहता हूँ कि (1) अपने मनका राज्य स्वराज्य है। (2) उसकी कुंजी सत्याग्रह, आत्मबल या करुणाबल है। (3) उस बल को आजमाने के लिए स्वदेशी को पूरी तरह अपनाने की जरूरत है। (4) हम जो करना चाहते हैं वह अंग्रेजों के लिए (हमारे मन में) द्वेष है इसलिए या उन्हें सजा देने के लिए न करें, बल्कि इसलिए करें कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। मतलब यह कि अंग्रेज अगर नमक- महसूल रद कर दें, लिया हुआ धन वापस कर दें, सब हिन्दुस्तानियों को बड़े-बड़े ओहदे दे दें और अंग्रेजी लश्कर हटा लें, तो हम उनकी मिलों का कपड़ा पहनेंगे, या अंग्रेजी भाषा काममें लायेंगे, या उनकी हुनर कलाका उपयोग करेंगे सो बात नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि वह सब दरअसल न करने जैसा है, इसलिए हम उसे नहीं करेंगे। मैंने जो कुछ कहा है वह अंग्रेजों के लिए द्वेष होने के कारण नहीं, बल्कि उनकी सभ्यता के लिए द्वेष होने के कारण कहा है।

कांग्रेस भाजपा के बीच तीन राज्यों में सीधा मुकाबला

अजय बोस

इस महीने शुरू होने जा रहे देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों ने लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा और हाल ही कांग्रेस के नेतृत्व में गठित विपक्षी गठबंधन %इंडिया% के बीच एक प्रकार से सेमी फाइनल का महत्व हासिल कर लिया है। तीन राज्यों-छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो दो राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस को सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दलों का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करती है, तो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा पर दबाव बढ़ेगा। लिहाजा ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए परीक्षा हैं कि वह कांग्रेस मुक्त भारत का अपना वादा पूरा कर पाने में सक्षम हो पाते हैं या नहीं।

पांच साल पहले हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस तेलंगाना और मिजोरम में बुरी तरह हार गई थी, जबकि छत्तीसगढ़ में उसे जबर्दस्त जीत मिली थी, और मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में उसने कुछ सीटों के अंतर से जीत हासिल कर तीन राज्यों में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया था। मगर मुश्किल से एक साल बाद ही बड़ी संख्या में विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के दलबदल के कारण भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता वापस हासिल करने में कामयाब रही।

लंबे समय तक ऐसा लगता रहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं सचिन पायलट के बीच अंदरूनी कलह का फायदा उठाकर भाजपा राजस्थान में भी वही कहानी दोहराने वाली है। पर लगता है कि गांधी परिवार और केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व, दोनों ने अपनी पिछली गलतियों से कड़वा सबक सीखा है। मिलनसार एवं राजनीतिक रूप से चतुर मल्लिकार्जुन खरगे जैसे पुराने योद्धा को पार्टी अध्यक्ष बनाने से बड़ा फर्क आया है। कांग्रेस के दोनों क्षेत्रीय क्षत्रपों एवं अन्य विपक्षी नेताओं से निपटने में बेहद प्रभावी

खरगे अब तक बिना किसी रुकावट के विधानसभा चुनावों के मौजूदा दौर में राजनीतिक सफर तय करने में कामयाब रहे हैं। गांधी परिवार ने उन्हें ऐसा करने का अधिकार दिया है।

भाजपा की अपनी समस्याएं हैं, जिन्हें उसे हल करना है। ये समस्याएं मुख्यत: केंद्रीय नेतृत्व द्वारा छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे क्षेत्रीय क्षत्रपों को चुनाव अभियान का नेतृत्व देने के प्रति अनिच्छा से उपजी हैं। गौर करना चाहिए कि ऐसी ही रणनीति के कारण कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश में भाजपा को सत्ता गंवानी पड़ी थी। इसलिए संकेत हैं कि अंतिम समय में केंद्रीय नेतृत्व ने इन तीनों नेताओं की नाराजगी दूर करने के प्रयास किए।

दरअसल, 2018 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा हाई कमान ने तीन बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह को न सिर्फ हाशिये पर डाल दिया था, बल्कि इस बार अंतिम क्षण तक यह निश्चित नहीं था कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। लेकिन अंतत: उन्हें टिकट दे दिया गया। इसके बावजूद भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं कर रही, जबकि कांग्रेस भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रही है।

इसी तरह, मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान भाजपा की जीत होने पर भी मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। एक बार फिर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस दुविधा में फंसा है कि चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाए बिना चौहान का कद कैसे छोटा किया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घटते प्रभाव ने इसे और जटिल बना दिया है, जिनके पूर्व वफादार अब फिर से कांग्रेस में लौट रहे हैं। राजस्थान में भाजपा के लिए राह तुलनात्मक रूप से आसान होनी चाहिए, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सत्ता विरोधी रुझान और नाराज प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट, दोनों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भाजपा यहां भी दुविधा में है कि राजनीतिक नुकसान उठाए बिना प्रभावी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को कैसे कमजोर किया जाए। पिछले महीने एक समय ऐसा लगा था कि भाजपा नेतृत्व वसुंधरा राजे के वफादारों को टिकट नहीं देने जा रहा। लेकिन राजे के तेवर को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने अपना रुख बदला और अंतिम क्षण में उनके वफादारों को इस उम्मीद में टिकट दिया कि इससे वह आश्वस्त होंगी।

इन तीनों चुनावी राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि भाजपा ने किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश नहीं किया है और वह प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, जबकि कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पहले से ही तय कर रखे हैं। अब देखना यह है कि इसका चुनावों में क्या असर पड़ता है। हिमाचल एवं कर्नाटक के नतीजों को देखते हुए भाजपा के लिए यह चिंताजनक होना चाहिए।

तेलंगाना और मिजोरम का उभरता चुनावी परिदृश्य भी केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। वहां हाल के महीनों में कांग्रेस ने उल्लेखनीय राजनीतिक बढ़त हासिल की है। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि भाजपा समेत विभिन्न दलों के नेता बड़ी संख्या में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मिजोरम में आदिवासी आबादी है, जिनमें से अधिकतर ईसाई हैं, जो पड़ोसी राज्य मणिपुर के कुकी समुदाय से जातीय संबंध साझा करते हैं। वे मणिपुर में कुकियों और देश के अन्य हिस्सों में ईसाइयों को निशाना बनाए जाने से क्षुब्ध हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले राजग से संबद्ध होने के बावजूद केंद्र सरकार का पर्याप्त विरोध न करने के कारण सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के प्रति राज्य में असंतोष है। इसका लाभ अगर कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट को चुनाव में मिले, तो आश्चर्य नहीं।

फिर भी यह देखना बाकी है कि क्या कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हुए अपने विरोधियों की कमजोरियों का फायदा उठा पाएगी? यह काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले हफ्तों में वह गति खोए बिना अपनी पकड़ बनाए रख सकती है या नहीं, क्योंकि अनुमान यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी रथ जब रफ्तार पकड़ेगा, तब शक्ति और संसाधनों के मामले में प्रभावी भाजपा को उसका फायदा मिलेगा।

अदालतों में तारीख पे तारीख का बढ़ता नासूर

विराग गुप्ता

दामिनी फिल्म के बाद पिछले 30 सालों में सुप्रीम कोर्ट में 25 प्रधान न्यायाधीश आने के बावजूद तारीख पे तारीख का मर्ज कायम है। जिला अदालतों में 4।41 करोड़, उच्च न्यायालयों में 61.7 लाख और सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 79 हजार मामले लंबित हैं। राज्यों और केंद्र सरकार में राजस्व विभाग, नगर पंचायत, आयकर और जीएसटी और सर्विस से जुड़े विवादों का तो इन आंकड़ों में लेखा-जोखा ही नहीं है। करोड़ों हैरान और परेशान लोगों के साथ अब सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने तारीख पे तारीख के बढ़ते मर्ज पर गंभीर चिंता जतायी है। सुप्रीम कोर्ट, 25 हाइकोर्ट और लगभग 20 हजार जिला स्तरीय अदालतों में सही और जल्द न्याय मिलने के संवैधानिक अधिकार का हनन होना खतरनाक होने के साथ चिंताजनक भी है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़े ही भावुक और संवेदनशील तरीके से जजों से इसके समाधान करने का निवेदन किया था। कुछ जरूरी बातों पर चिंतन के साथ त्वरित कार्रवाई हो, तो न्याय की गाड़ी पटरी पर आ सकती है। रसूखदार लोगों के खिलाफ सामान्यत: कोई कार्रवाई नहीं होती और अगर संयोग से मामला दर्ज हो जाए, तो रईस लोगों को बड़े वकीलों के दम पर झटपट राहत मिल जाती है, लेकिन आम जनता के लिए न्यायिक व्यवस्था जटिल हो गयी है, जिसका सजीव चित्रण दामिनी के साथ अंधा कानून जैसी फिल्मों में किया गया है। जिला अदालतों में 80 फीसदी मामले यानी 3.31 करोड़ मुकदमे फौजदारी के हैं, जिनमें पुलिस यानी सरकार एक पक्षकार है। इनमें एक करोड़ मुकदमे पुलिस की वजह से लंबित हैं। लगभग 19 लाख मामलों में चार्जशीट दायर होने के बावजूद पुलिस ने दस्तावेज जमा नहीं किये, 33 लाख मामलों में गवाह की पेशी नहीं हो पा रही और 45 लाख मामलों में जमानत के बाद फरार आरोपियों को पुलिस अदालत में पेश नहीं कर पा रही। सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, जिनकी वैकेंसी की खबरें सुर्खियां बन जाती हैं, जबकि जिला अदालतों में 5850 से ज्यादा रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरने की कोशिश करने के बजाय जजों की संख्या में बढ़ोतरी की एकेडमिक बहस का चलन बढ़ गया है। जिला अदालतों में जजों के पास जरूरी स्टॉफ और सुविधाएं नहीं हैं। सरकार न्यायिक सिस्टम पर जीडीपी का सिर्फ 0.1 फीसदी यानी हजार में एक रुपया खर्च करती है। इसलिए जिला अदालतों में लोगों को तारीख पे तारीख के नासूर से मुक्ति नहीं मिल पा रही। जिला अदालतों में संयोग से न्याय मिल भी जाए, तो मामला हाइकोर्ट में अटक जाता है। पच्चीस हाइकोर्टों में 61.70 लाख मामलों में 44 लाख सिविल और 17 लाख फौजदारी के मुकदमे लंबित हैं। दूसरी तरफ हाइकोर्टों में लगभग 332 जजों के पद रिक्त हैं। संविधान के अनुसार, बेकसूर लोगों को जेल में बेवजह बंद रखना पूरी तरह से गलत है। सिविल मामलों में स्टे लेने के बाद वादी पक्ष वकीलों के माध्यम से मुकदमों को लटकाने लगता है और जजों को भी मामले में निर्णायक फैसला देने की कोई जल्दी नहीं होती। नेशनल ज्यूडीशियल डाटा ग्रिड के अनुसार, 31 लाख से ज्यादा मुकदमों की गाड़ी स्टे के बाद से अटकी हुई है। सरकारी विभागों में गलत नियम या तरीके से नियुक्ति हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देती है। केंद्र सरकार के अनुसार पिछले आठ सालों में जजों की नियुक्ति के लिए बनी नियमावली में जरूरी संशोधन नहीं होने के बावजूद सैंकड़ों जजों की नियुक्ति हुई है। जजों की मनमाने तरीके से हो रही नियुक्ति के पीछे नेता, अफसर, जज और सीनियर वकीलों का बड़ा गठजोड़ है। नेशनल लॉ स्कूल की एसोसिएट प्रोफेसर अर्पणा चंद्रा की पुस्तक कोर्ट ऑन ट्रायल के अनुसार कई सीनियर वकील रोजाना 10-15 मामले कर करोड़ों की फीस कमा लेते हैं। इस रिसर्च के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट, जो संविधान अदालतें हैं, वहां पर गंभीर संवैधानिक बहस के बजाय फिजूल के मामलों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे मामलों में मेरिट की जगह चेहरे पर ज्यादा जोर हो गया है, जो कानून के शासन के लिहाज से गलत और खतरनाक है। जिला जज को फांसी देने का अधिकार है, तो फिर जमानत के बहुतायत मामले हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाने चाहिए? इस वजह से जनता के मामले दरकिनार होने के साथ जिला अदालतों के जजों के अधिकारों का भी हनन होता है।

राजनीतिक गठबंधन पहुंचने लगे हैं बिखरने के कगार पर!

राजकुमार सिंह

अक्सर राजनीतिक गठबंधन चुनाव के लिए बनाए जाते हैं, पर देश के दोनों बड़े गठबंधनों- एनडीए और 'इंडिया' में नवंबर में हो रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव ही तकरार का कारण बन रहे हैं। चंद महीने पहले ही विपक्ष के 28 दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के विरुद्ध नया गठबंधन- इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया) बनाया था। भाजपा ने भी अपने पुराने गठबंधन- एनडीए का रजत जयंती वर्ष में विस्तार करते हुए कुनबा 38 दलों तक पहुंचा दिया था। इशारा अगले लोकसभा चुनावों की ओर था, मगर इस बीच विधानसभा चुनाव की परीक्षा में ही दोनों गठबंधन फेल होते नजर आ रहे हैं। जिन पांच राज्यों में नवंबर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें से दो- तेलंगाना और मिजोरम में जिन क्षेत्रीय दलों की सरकार है, वे किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं। वहां कांग्रेस-भाजपा का टकराव ज्यादा मायने नहीं रखता। इसलिए सारा फोकस शेष तीन राज्यों- मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर है, जहां की सत्ता के लिए कांग्रेस-भाजपा में ही मुख्य मुकाबला होता रहा है। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस से सत्ता छीननेवाली आप इंडिया गठबंधन में शामिल है, पर उसने मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में दर्जनों सीटों पर 'इंडिया' घटक दलों में ही मुकाबले की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में अभी तक सपा और जद यू ने तो कांग्रेस के लिए चुनावी चुनौती के संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन आप वहां भी ताल ठोंक रही है। राजस्थान में भी सपा और रालोद की मौजूदगी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है। राजस्थान में भाजपा के मित्र दल भी उसके लिए मुश्किलें पेश कर रहे हैं। पिछला लोकसभा चुनाव भाजपा से गठबंधन में लड़े नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल की रालोपा अब यूपी के चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी जैसे छोटे दलों के साथ मिलकर अलग ताल ठोंक रही है। राजस्थान में भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने में जजपा, लोजपा और शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट भी पीछे नहीं है। हरियाणा सरकार में भाजपा की जूनियर पार्टनर जजपा एनडीए का हिस्सा है, पर राजस्थान में गठबंधन न हो पाने पर 30 सीटों पर ताल ठोंक रही है। जजपा चौधरी देवीलाल के परिवार के एक धड़े की पार्टी है, जिनका राजस्थान के कुछ हिस्सों में असर रहा। बिहार में जिन चिराग पासवान ने भाजपा का हनुमान बन कर पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जद यू को समेटने में बड़ी भूमिका निभाई, उनका लोजपा गुट भी राजस्थान में अलग ताल ठोंक रहा है। दोस्तों के बीच ही टकराव चुनावी परिदृश्य को तो दिलचस्प बना ही रहा है, गठबंधनों के भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा रहा है।

डबल इंजन सरकार की विफलता का सबब है मणिपुर की हिंसा

रामचंद्र गुहा

बीते पखवाड़े दो खबरें सुर्खियों में थीं - विश्व कप क्रिकेट के मैच और गाजा में इस्राइल की निरंकुश बमबारी। इनमें से पहली या दूसरी खबर के प्रति हमारे आकर्षण का ही नतीजा रहा कि एक दुखद घटनाक्रम से जुड़ी तिथि हमारे अनजाने ही निकल गई - मणिपुर हिंसा के छह महीने बीत गए। मणिपुर में हिंसा शुरू होने के कुछ महीने बाद मैंने द टेलीग्राफ में लिखा था, और एक वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए भी कहा था कि हमें इस हिंसा की गंभीरता समझनी चाहिए। अपने इस कॉलम में मैं मणिपुर संकट पर, शायद व्यर्थ ही, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूंगा, जो सातवें महीने में प्रवेश कर चुका है।

मणिपुर के प्रति मेरी उत्सुकता शुरुआत में एक इतिहासकार की उत्सुकता थी कि 1949 में स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने के बाद से उसकी अब तक की यात्रा कैसी रही है। मणिपुर के प्रति मेरी रुचि कुछ साल पहले उस राज्य की यात्रा करने पर बढ़ी, जब मैं उसके प्राकृतिक सौंदर्य, संगीत और नृत्य की उसकी समृद्ध परंपरा, वहां की स्त्रियों की स्वतंत्रता और तीन मुख्य नस्लीय समूहों- मैतेई, नगा कुकी और कुकी के एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी संबंधों के बारे में देख-जानकर दंग रह गया। इतिहासकार और पर्यटक, दोनों ही भूमिकाओं में मैं मणिपुर में व्याप्त तनावों को देख पाया था, लेकिन वहां का मौजूदा संकट न सिर्फ अभूतपूर्व है, बल्कि सोचा भी नहीं गया था कि संकट यह रूप लेगा। पिछले कुछ महीनों से मैतेई और कुकी उग्रवादी एक दूसरे से दुश्मनों की तरह पेश आ रहे हैं। वहां जो हिंसा हुई, उसे ऑनलाइन और भी भीषण रूप दिया गया।

जैसा कि हम जानते हैं, गोदी मीडिया ने मणिपुर हिंसा के ब्योरों को छिपाया और उनकी अनदेखी की। सौभाग्य से कुछ स्वतंत्र वेबसाइटों ने हमें बताया कि वहां वास्तव में

हो क्या रहा है। मैंने भी वहां रहने वाले अपने सहयोगियों के संपर्क में रहते हुए उनसे लगातार बातचीत की। मेरा यह विश्लेषण इन्हीं सबूतों के आधार पर है। ऐसा नहीं है कि मई, 2023 से पहले राज्य में मैतेई और कुकी सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते थे। उनका धर्म अलग है, ज्यादातर कुकी ईसाई हैं, जबकि अधिसंख्य मैतेई हिंदू हैं। कुकी पहाड़ों में रहते हैं, जबकि मैतेई का इंफाल घाटी में वर्चस्व है। मैतेई राजनेता जिस वर्चस्ववादी रवैये का प्रदर्शन करते थे, वह कुकियों को क्षुब्ध करता था। जबकि मैतेई शिकायत करते थे कि कुकियों को अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा मिला हुआ है, उससे उन्हें नौकरी मिलने में आसानी होती है।

नस्लीय और धार्मिक हिंसा हमारे यहां आम है। इसके बावजूद हिंसा के स्तर और ध्रुवीकरण के कारण मणिपुर की हिंसा बेहद गंभीर है। स्वतंत्र विश्लेषकों द्वारा इकट्ठा किए गए सबूत बताते हैं कि इस हिंसा में कुकी को अपेक्षाकृत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि मैतेई समुदाय के पास सत्ता की ताकत है, पुलिस और नौकरशाही मैतेई राजनेताओं को ही रिपोर्ट करती है। इस विषमता से जुड़ा एक तथ्य यह है कि राज्य में, एक आंकड़े के मुताबिक, दो सौ से भी गिरजाघरों को ध्वस्त कर दिया गया है।

राज्य की इस बदहाली के लिए तीन लोगों को अपनी जवाबदेही स्वीकारनी ही चाहिए। इनमें से पहले हैं राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह, जो स्पष्ट रूप से मैतेई समुदाय के पक्ष में दिखे। बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार का वैचारिक पक्षपात इसकी प्रशासनिक अक्षमता से पूरी तरह मेल खाता दिखा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, हिंसा शुरू होते ही राज्य सरकार ने उग्रवादियों को बड़ी मात्रा में हथियार लूटने की अनुमति ही नहीं दी, बल्कि प्रोत्साहित भी किया। हिंसा के छह महीने से अधिक हो चुके हैं, लेकिन लूटे गए हथियारों का मामूली हिस्से की ही बरामदगी हुई है।

मणिपुर की इस त्रासदी के लिए जो दूसरे व्यक्ति जिम्मेदार हैं, वह हैं केंद्रीय गृह मंत्री, जिन्होंने राज्य के एक छोटे-से दौरे के अलावा हिंसा रोकने के लिए शायद ही कोई प्रभावी कदम उठाया। इसके बजाय उन्होंने उन राज्यों में मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च की, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तीसरे व्यक्ति हैं खुद प्रधानमंत्री, जिन्होंने राज्य का दौरा ही नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने मुख्यमंत्री और अपने गृह मंत्री को अपनी मनमर्जी का करने दिया। चाहे यह संवेदनहीनता हो या फिर दंभ, लेकिन मणिपुर के लोगों के प्रति कोई रुचि न दिखाना देश के प्रधानमंत्री के लिए शोभनीय नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर मणिपुर का दौरा करते और पहाड़ तथा घाटी, दोनों जगह जाते, तो इससे यह संदेश जाता कि उन्हें मणिपुर की फिक्र है। इससे संभवत: दोनों हिंसक समुदायों के नेताओं के बीच बातचीत और मेलजोल की शुरुआत भी हो सकती थी। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के पक्षपाती आचरण का कारण शायद यह है कि मैतेई समुदाय के वर्चस्ववाद का संदेश देकर वह राज्य की सत्ता में बने रह सकते हैं।

भारत को एक सूत्र में पिरोने में सफल रही है सनातन संस्कृति

प्रह्लाद सबनानी

भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और परम्पराएं विश्व में सबसे अधिक प्राचीन मानी जाती है। भारतीय संस्कृति को विश्व की अन्य संस्कृतियों की जननी भी माना गया है। भारत की संस्कृति और सभ्यता आदि काल से ही अपने परम्परागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। भारत में गीत संगीत, नाटक परम्परा, लोक परम्परा, धार्मिक संस्कार, अनुष्ठान, चित्रकारी और लेखन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। इसे संजोने, संवारने और निखारने का महती प्रयास हाल ही के समय में बहुत मजबूती के साथ किया जा रहा है। विशेष रूप से पिछले एक दशक में भारत की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं जिससे न केवल विश्व के लोगों को देश के माटी की सौंधी खुशबू मिली है बल्कि पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति को जानने एवं समझने का प्रयास भी कर रही है। भारत का अतीत वर्तमान से भी सुंदर एवं प्रभावशाली रहा है।

भारत ने राजनैतिक स्वतंत्रता 75 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर ली थी, परंतु भारत की सनातन संस्कृति आदि काल से चली आ रही है एवं लाखों वर्ष पुरानी है। भारत को 'सोने की चिड़िया' के रूप में जाना जाता रहा है और भारतीय सनातन संस्कृति का लोहा पूरे विश्व ने माना है। धर्म, दर्शन, विरासत, तीज, त्यौहार, जायका और अनेकता में एकता के दर्शन करने को पूरी दुनिया भारत की ओर आकर्षित होती रही है। भारत को देव भूमि भी कहा गया है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है और यह समर्पण की भूमि है।

भारत आदि काल से ही एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, यह मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत के कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास बताया जाता है। हाल ही के कुछ वर्षों में भारत के आर्थिक विकास में विरासत पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है और भारत में आर्थिक विकास के साथ ही सांस्कृतिक विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। जिसके चलते अन्य देशों की तुलना में भारत की आर्थिक विकास दर मजबूत बनी हुई है। बल्कि अब तो अन्य कई देश, विकसित देशों सहित, भी अपने आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समस्याओं के हल हेतु एवं अपने आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से भारतीय सनातन संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

हाल ही के समय में भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, संवारने और उसकी संवृद्धि के लिए विशेष रूप से पिछले दशक के दौरान अथक प्रयास किए गए हैं। हजारों वर्षों की भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि कितने ही झंझावात क्यों न आए परंतु भारतीय सनातन संस्कृति अटूट रही। हालांकि कुछ देशों, जैसे ग्रीक, यूनान, ईरान आदि, की तो सभ्यताएं ही समूल नष्ट हो गईं। भारत में अभी हाल ही में आजादी के 75 वर्षों के बाद अमृत काल मनाया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को प्रारम्भ हुई। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की गिनती शुरू हुई थी जो उत्सवों के साथ निरंतर गतिमान रही। इस बीच उत्सवों की लम्बी श्रृंखला चली और 15 अगस्त 2023 तक यह

यात्रा निर्बाध गति से चलती रही। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान 166,000 से अधिक कार्यक्रम देश और दुनिया में आयोजित किए गए। जिसमें हर घर तिरंगा, वन्दे भारतम, कलांजलि जैसे कई बड़े कार्यक्रम भी शामिल रहे।

अमृत महोत्सव के पांच स्तम्भ हैं- स्वतंत्रता संग्रामञ्च 75, विचारञ्च 75, समाधानञ्च 75, कार्यञ्च 75, उपलब्धियांञ्च 75। जनभागीदारी से मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव, देश की इन 75 वर्षों की उपलब्धियों को पूरी दुनिया के सामने रखने का एक प्रयास है और इसके साथ ही अगले 25 वर्षों के लिए संकल्पों की रूपरेखा भी रखी जा रही है।

भारतीय सनातन संस्कृति ने न केवल भारत को एकता के सूत्र में पिरोया है बल्कि पूरे विश्व को ही भारत के साथ जोड़ा है। अब तो भारत में 'एक भारत- श्रेष्ठ भारत' के रूप में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जा रहा है। भारत ने जी-20 समूह के देशों की अपनी अध्यक्षता के दौरान कई अतुलनीय कार्य किए हैं। पिछले लगभग एक वर्ष के अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सदस्य देशों की 200 से अधिक बैठकों का भारत के विभिन्न शहरों में आयोजन कर भारत ने पूरी दुनिया के समस्त देशों को चौंका दिया है। इस दौरान, भारत ने पूरी दुनिया को ही अपनी महान गौरवशाली सनातन संस्कृति, वैभवशाली विरासत, आध्यात्मिक क्षेत्र, आर्थिक विकास, आदि का परिचय देने में सफलता हासिल की है।

भारत ने हाल ही के वर्षों में अपनी आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को हल करने एवं अपनी आर्थिक विकास दर को तेज करने में जो सफलता पाई है वह मुख्य रूप से भारत की सनातन संस्कृति एवं परम्पराओं का पालन करते हुए ही प्राप्त की जा सकी है। इसके ठीक विपरीत विशेष रूप से कोरोना महामारी के बाद से विश्व के कई विकसित देश अभी तक कई प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। पूंजीवाद पर आधारित आर्थिक नीतियों के पालन से पश्चिमी देशों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। विकसित देशों में आज परिवार की प्रधानता एक तरह से समाप्त हो चुकी है। इस संदर्भ में यहां विशेष रूप से अमेरिका की स्थिति का उदाहरण दिया जा सकता है। अमेरिका में आज सामाजिक तानाबाना छिन्न-भिन्न हो चुका है। दंपतियों में तलाक की दर बहुत अधिक हो गई है जिसके चलते बच्चे केवल अपनी मां के पास रह जाते हैं एवं बड़ी संख्या में बच्चों को अपने पिता के बारे में जानकारी ही नहीं है।

विकसित देशों में पारिवारिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने के कारण बुजुर्गों को सरकार की मदद पर निर्भर रहना होता है। अत: इन देशों की सरकारों को सामाजिक सुविधाओं पर भारी भरकम राशि खर्च करनी होती है। कई विकसित देशों में तो बुजुर्गों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है जिसके चलते इन देशों को अपने बजट का बहुत बड़ा भाग सामाजिक सुविधाओं पर खर्च करना पड़ रहा है। फ्रांस अपने कुल बजट का 31 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुविधाओं पर खर्च कर रहा है, इसी प्रकार इटली 28 प्रतिशत, जर्मनी 26 प्रतिशत एवं अमेरिका 19 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुविधाओं पर खर्च कर रहा है। सामाजिक सुविधाओं पर भारी भरकम खर्च के कारण इन देशों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है एवं इन देशों में प्रति व्यक्ति औसत ऋण बहुत अधिक हो गए हैं। अमेरिका में तो कुल सकल घरेलू उत्पाद का 136 प्रतिशत कर्ज लिया जा चुका है। आज ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु भी कुछ देशों को कर्ज लेना पड़ता है। पश्चिमी दर्शन की विचारधारा के ठीक विपरीत, भारतीय संस्कृति के अनुसार, व्यक्तिवाद के ऊपर परिवार, समाज, राष्ट्र, सृष्टि एवं परमेशटी को क्रमश: माना गया है। संयुक्त परिवार के प्रचलन के कारण बुजुर्गों की देखभाल परिवार में ही होती है एवं सरकार के बजट पर इस संदर्भ में बहुत अधिक बोझ नहीं आता है। भारतीय सनातन संस्कृति का पालन करते हुए भारत के आर्थिक विकास को देखकर अब विकसित देश भी भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हुए इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं ताकि वे अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समस्याओं को हल कर सकें। कुल मिलाकर अब भारतीय आर्थिक दर्शन ही पूरे विश्व को बचा सकता है, क्योंकि वह कर्म आधारित है और एकात्म मानवता पर केंद्रित है।

छग, मप्र और राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार?

सी वोटर के फाइनल सर्वे से भाजपा को झटका

7 नवंबर से तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। यूं तो इन सभी राज्यों के चुनाव खासा महत्वपूर्ण हैं लेकिन राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की नजर तीन राज्यों पर अटकी हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। ऐसे में एक ताजा सर्वे सामने आया है जिसमें तीनों राज्य के लोगों ने अपना मूड बताया है।

छत्तीसगढ़ में खिलेगा कमल या कांग्रेस मारेगी बाजी?- छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। सूबे में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 46 का जादुई आंकड़ा पार करना होगा। सर्वे के मुताबिक, राज्य में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। सर्वे की मानें तो 90 सीटों में से 45 से 51 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। वहीं भाजपा के खाते में 36 से 42 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं।

राज्य में कांग्रेस को 45 परसेंट वोट मिल सकता है। वहीं भाजपा को 43 परसेंट और अन्य को 12 परसेंट वोट मिल सकता है।

मप्र में कमल या कमलनाथ?- मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। सूबे में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 116 का जादुई आंकड़ा पार करना होगा।

एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने फाइनल सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक, राज्य में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। जी हां... सर्वे की मानें तो 230 में 118 से 130 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। वहीं भाजपा के खाते में 99 से 111 और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। राज्य में कांग्रेस को 44 फीसदी वोट मिल सकता है। वहीं भाजपा को 42 परसेंट और अन्य को 14 फीसदी वोट मिल सकता है।

राजस्थान में मोदी मैजिक या गहलोत का जादू?-राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। सूबे में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 101 का जादुई आंकड़ा पार करना होगा। सर्वे के मुताबिक, राजस्थान में भाजपा सरकार बना सकती है। सर्वे की मानें तो 200 सीटों में 114 से 124 सीटों पर भाजपा कब्जा कर सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 67 से 77 सीटें और अन्य के पास 5 से 13 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान में भाजपा को 45 परसेंट वोट मिल सकता है। वहीं कांग्रेस को 42 परसेंट और अन्य को 13 परसेंट वोट मिल सकता है।

सर्वे से भाजपा को क्यों झटका?- सर्वे की मानें तो तीन में से केवल एक राज्य में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है। हालांकि राजस्थान में भाजपा कांग्रेस से आगे दिख रही है।

पहले चरण में किसके सामने कौन? छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस के इन दिग्गजों पर सबकी नजर

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। सूबे की 90 सीटों वाली विधानसभा के लिए 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। इन 20 सीटों में से 12 एसटी के लिए और 1 सीट एससी के लिए रिजर्व है। पहले चरण की सभी सीटें नक्सल प्रभावित इलाके में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता डॉ रमन सिंह हाई प्रोफाइल सीट राजनंदगांव से मैदान में हैं। सूबे में प्रमुख प्रतिद्वंदी भाजपा कांग्रेस ने इन सभी 20 सीटों पर कांटे की टक्कर वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इन सभी 20 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट इस प्रकार है -

सीट	कांग्रेस	भाजपा
पंडरिया	नीलकंठ चंद्रवंशी	भावना बोहरा
कवर्धा	मोहम्मद अकबर	विजय शर्मा
खैरागढ़	यशोदा वर्मा	विक्रांत सिंह
डोंगरगढ़ (एससी)	हर्षिता स्वामी बघेल	विनोद खांडेकर
राजनंदगांव	गिरीश देवांगन	डॉ रमन सिंह
डोंगरगांव	दलेश्वर साहू	भरत लाल वर्मा
खुजली	भोला राम साहू	गीता घासी साहू
मोहला मानपुर(एससी)	इंद्र शाह मांडवी	संजीव साहा
अंतागढ़ (एससी)	रूप सिंह पोते	विक्रम उसेंडी
भानुप्रतापुर (एससी)	सावित्री मांडवी	गौतम उइके
कांकेर (एससी)	शंकर ध्रुव	आशाराम नेताम
केशकाल (एससी)	संत राम नेताम	नीलकंठ टेकाम
कोंडागांव(एससी)	मोहन लाल मरकम	सुश्री लता उसेंडी
नारायणपुर (एससी)	चंदन कश्यप	केदार कश्यप
बस्तर(एससी)	लखेश्वर बघेल	मनीराम कश्यप
जगदलपुर	जितिन जायसवाल	किरण सिंह देव
चित्रकोट (एससी)	दीपक बैज	विनायक गोयल
दंतेवाड़ा (एससी)	के छविंद्र महेंद्र कर्मा	चेतराम अरामी
बीजापुर(एससी)	विक्रम मांडवी	महेश गागड़ा
कोंटा (एससी)	कवासी लखमा	सोयम मुका

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होगा। 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। काउंटिंग 3 दिसंबर को होगी। पहले चरण की वोटिंग के लिए शनिवार देर शाम मतदान सामग्री के साथ टीमों को बूथ पर रवाना किया गया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में एयरलिफ्ट करके भी पहुंचाया जा रहा है। नक्सल प्रभावित सीटों पर सुरक्षा व्यवस्था चक चौबंद की गई है।

अंजोरा जो दो विधानसभा सीटों पर चुनता है विधायक, क्या है वजह?

छत्तीसगढ़ का अंजोरा गांव सूबे का ऐसा गांव है जहां दो निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार अपने लिए वोट मांगने पहुंच रहे हैं। इस गांव के मतदाता पहले चरण में होने वाले राजनांदगांव सीट और दूसरे चरण में दुर्ग ग्रामीण सीट के लिए मतदान करेंगे। राज्य में 90 विधानसभा सीट के लिए दो चरणों में सात और 17 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण में 20 तथा दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान होगा। पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लिए प्रसिद्ध अंजोरा गांव दुर्ग और राजनांदगांव जिलों की सरहद के बीच है।

यह राज्य का एक ऐसा गांव है जहां के मतदाता दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान करेंगे।

इस गांव का आधा हिस्सा राजनांदगांव विधानसभा सीट के अंतर्गत है जहां पहले चरण में सात नवंबर को मतदान होगा तथा आधा हिस्सा दुर्ग ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहां दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा।

अंजोरा गांव को एक मुख्य सड़क ने दो हिस्सों में बांट दिया है। सड़क के एक ओर दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के निवासी रहते हैं और दूसरी ओर राजनांदगांव क्षेत्र के निवासी। यह गांव दो ग्राम पंचायतों अंजोरा ग्राम पंचायत (राजनांदगांव) और अंजोरा ख ग्राम पंचायत (दुर्ग) के अंतर्गत भी आता है। अंजोरा गांव दुर्ग शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर और राजनांदगांव शहर के बीच मुंबई-हावड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर स्थित है। गांव की आबादी लगभग पांच हजार है। अंजोरा पंचायत (राजनांदगांव) की सरपंच अंजू साहू कहती हैं कि चुनाव के दौरान अक्सर गांव के लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार प्रचार के लिए गांव आते हैं। पूरे गांव में उम्मीदवारों के पोस्टर और बैनर देखे जा सकते हैं, चाहे वे (दोनों में से) किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हों। इसलिए यह कहा जाता है कि इस गांव से दो विधायक (दो निर्वाचन क्षेत्रों के लिए) चुने जाते हैं।

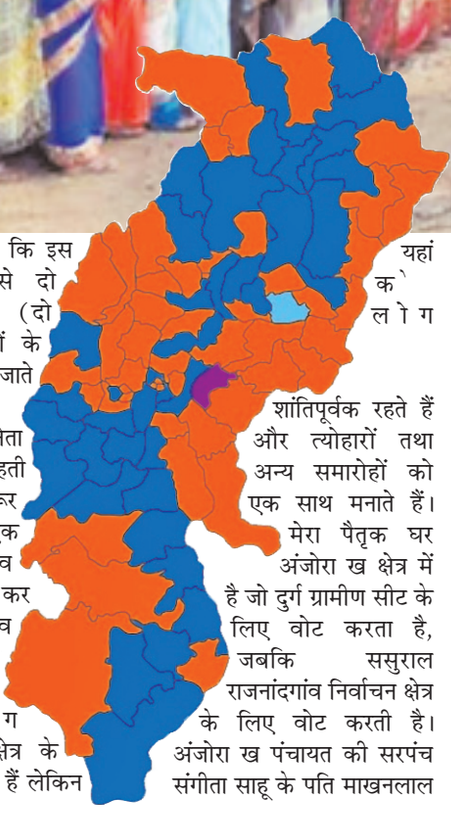

कांग्रेस नेता अंजू साहू कहती हैं कि यह जरूर है कि एक सड़क ने गांव को विभाजित कर दिया है। चुनाव के दौरान लोग अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए वोट देते हैं लेकिन यहां के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं और त्योहारों तथा अन्य समारोहों को एक साथ मनाते हैं। मेरा पैतृक घर अंजोरा ख क्षेत्र में है जो दुर्ग ग्रामीण सीट के लिए वोट करता है, जबकि ससुराल राजनांदगांव निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोट करती है। अंजोरा ख पंचायत की सरपंच संगीता साहू के पति माखनलाल साहू ने बताया कि राजनांदगांव जिले का गठन 1973 में दुर्ग जिले (तत्कालीन मध्य प्रदेश) से अलग कर किया गया था।

तब से गांव दो पंचायतों में विभाजित हो गया। विधानसभा सीटों के लिए परिसीमन भी इस तरह से किया गया था कि गांव का आधा हिस्सा एक निर्वाचन क्षेत्र में तथा आधा हिस्सा अन्य क्षेत्र में पड़े।

अंजू साहू ने बताया कि गांव में ऐसे भी परिवार हैं, जिनके आधे सदस्यों को राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए और आधे सदस्यों को दुर्ग ग्रामीण के लिए मतदान करना होता है। राजनांदगांव और दुर्ग ग्रामीण राज्य के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में से हैं। राजनांदगांव सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और दुर्ग ग्रामीण सीट से राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू चुनाव मैदान में हैं।

भाजपा ने रमन सिंह को उनकी मौजूदा राजनांदगांव सीट से मैदान में उतारा है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के मौजूदा अध्यक्ष गिरीश देवांगन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दुर्ग ग्रामीण सीट पर कांग्रेस ने अपने अहम ओबीसी नेता एवं मंत्री ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारा है जिनका मुकाबला भाजपा के नए चेहरे ललित चंद्राकर से है।

केशकाल में रोचक मुकाबला, इस सीट पर किसी ने नहीं बनाई जीत की तिकड़ी

कांग्रेस के लिए राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां चुनावी सभा ले चुके हैं। भाजपा के लिए प्रचार के अंतिम दिन रविवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी की सभा हुई है।

इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत केशकाल, विश्रामपुरी और फरसगांव आते हैं। यहां 2013 से लगातार कांग्रेस का कब्जा है।

आजादी के बाद पिछले 15 विधानसभा चुनावों में केशकाल सीट का रिकार्ड रहा है कि यहां कोई भी दल जीत की हैट्रिक नहीं बना पाया है। लगातार दो जीत का ही रिकार्ड रहा है। इस बार के चुनाव में यह रिकार्ड बरकरार रहेगा या टूटेगा इसका फैसला सात नवंबर को चुनाव में मतदाता करेंगे।

मतदाता खामोश हैं इसलिए दोनों दलों में कोई भी सौ फीसद जीत का दावा नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र को आगे कर वोट मांग रही है। किसानों की कर्ज माफी और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को प्रमुख मुद्दा बनाकर जनता के बीच कांग्रेसी जा रहे हैं।

नीलकंठ टेकाम को बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। दूसरी ओर भाजपा अपने प्रत्याशी के कोंडागांव में कलेक्टर रहते क्षेत्र के विकास के लिए कराए गए कामों को गिना रही है। टेकाम के प्रशासनिक अनुभव का पासा फेंका गया है।

भाजपा द्वारा कांग्रेस पर विकास को अवरूद्ध करने और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों की बात का प्रचार कर कांग्रेस प्रत्याशी पर व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी की ओर से केशकाल क्षेत्र के लिए अलग से अपना संकल्प पत्र जारी किया गया है। बेरोजगारी को भी पार्टी ने एक मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश की है।

दो लाख से अधिक मतदाता- केशकाल विधानसभा क्षेत्र में 290 मतदान केंद्र और दो लाख छह हजार 304 मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। 18 से 39 साल आयुवर्ग के मतदाताओं की संख्या कुल संख्या की लगभग आधी है। ये युवा मतदाता चुनाव में निर्णायक भूमिका तय करेंगे। इस सीट पर पिछले चुनाव में लगभग अस्सी फीसद मतदान दर्ज किया गया था।

विकास का मुद्दा गायब- चुनाव में विकास का मुद्दा गायब है। प्रत्याशियों और दोनों पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप की पूरे चुनाव प्रचार अभियान में हावी रहे हैं। मतदाता भी मूकदर्शक बने हुए हैं ये अपनी चुप्पी सात नवंबर को मतदान के दिन तोड़ेंगे। केशकाल घाट की खस्ताहाल स्थिति पर दोनों दलों के अपने दावे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा होने से कांग्रेस राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित केशकाल घाट की खराब स्थिति के लिए केंद्र की भाजपा सरकार को दोषी ठहरा रही है तो भाजपा चुनाव जीतने पर बाइपास मार्ग का जल्दी निर्माण कराने का भरोसा दिला रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के अपने छोटे-छोटे मुद्दे हैं लेकिन दोनों दलों की घोषणाओं, गारंटियों और संकल्पों के आगे इनकी आवाज नक्कारखाने की तूती साबित हुई है। हकीकत यह भी है कि यहां भाजपा से प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दलीय प्रत्याशियों के चेहरों पर ही चुनाव के लिए ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है।

बेरोजगारी बना सबसे बड़ा मुद्दा, वोटिंग में इन मुद्दों की भी होगी अहम भूमिका

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा के लिए 7 नवंबर को पहले चरण में वोटिंग होगी. इसके साथ ही रविवार की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया. ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इस बार नक्स प्रभावित इस राज्य की जनता का क्या है मूड है और प्रदेश की जनता किस मुद्दे पर वोट करने जा रही है. इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए सीएसडीएस लोकनीति और एनडीटीवी की टीम ने राज्य में चुनाव पूर्व सर्वे किया. इस सर्वे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है.

बेरोजगारी और महंगाई है बड़े मुद्दे- राज्य सरकार की ओर से देश में सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में होने के दावों बीच राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है. सीएसडीएस लोकनीति और एनडीटीवी के सर्वे में 28 प्रतिशत लोगों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट डालने की बात कही. वहीं, विकराल होती जा रही महंगाई, बेरोजगारी के मुकाबले उतना बड़ा मुद्दा तो नहीं है, लेकिन यह 14 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर है.

गरीबी भी है बड़ा मुद्दा- राज्य के चुनाव में गरीबी भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है. राज्य के 12 प्रतिशत लोगों ने गरीबी के मुद्दे पर वोट डालने की बात कही है. वहीं, पीने के पानी की समस्या भी राज्य में 8 प्रतिशत लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है. यानी प्रदेश की 8 जनसंख्या पीने के पानी की उपलब्धता के आधार पर वोट डालने जा रही है.

किसान और विकास नहीं बन पाया बड़ा मुद्दा- धान का कटोरा कहे जाने वाले इस प्रदेश में किसानों की समस्या इस चुनाव में मुद्दा बनता नजर नहीं आ रही है. मात्र 6 प्रतिशत जनता ने ही किसानी संकट को एक बड़ा मुद्दा मानते हुए इसके आधार पर वोटिंग करने की बात कही है. वहीं, विकास का मुद्दा भी इस चुनाव में पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है. सीएसडीएस लोकनीति और एनडीटीवी के सर्वे में मात्र 6 प्रतिशत लोगों ने ही विकास को एक बड़ा मुद्दा मानते हुए विकास के आधार पर वोटिंग की बात कही. वहीं, 26 प्रतिशत जनता ने अलग-अलग स्थानीय मुद्दे पर वोटिंग की बात कही है. अब देखना ये होगा कि चुनाव में ये मुद्दे कितने प्रभावी साबित होते हैं.

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

अयोग्य घोषित हो सकती हैं महुआ मोइत्रा!

नईदिल्ली। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पूछताछ के लिए पैसे के आरोपों की जांच कर रहा संसदीय पैनल अब अपनी मसौदा रिपोर्ट को अपनाने के लिए 9 नवंबर को बैठक करेगा। पहले यह 7 नवंबर को आयोजित होने वाली थी। विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली लोकसभा की आचार समिति भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच पूरी होने के बाद मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी। इसके बाद वह मामले में कार्रवाई की अनुशंसा करेगी। 2 नवंबर को समिति की आखिरी बैठक में हंगामेदार दृश्य देखने को मिले। मोइत्रा गवाही देने के लिए पैनल के सामने आए थे, गुस्से में बाहर चले गए। उन्होंने आरोप लगाया था कि बैठक में जो कुछ हुआ वह कहावतपूर्ण वस्त्रहरण था। 15-सदस्यीय नैतिक पैनल में भाजपा के सदस्य बहुमत में हैं, जो मोइत्रा के खिलाफ आरोपों पर गंभीर नजरिया रख सकते हैं।

अशोक गहलोत ने सदरपुरा से दाखिल किया नामांकन

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सदरपुरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले गहलोत ने अपनी बहन का आशीर्वाद लिया। नामांकन भरने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रथम सेवक के रूप में कर्तव्यों का पालन किया है। सीएम ने कहा, मैंने जोधपुर में अपने अनुभव से जो कुछ भी सीखा है, उसे राजस्थान की सेवा के लिए दिया है। अब यह लोगों को तय करना है। गहलोत ने आगे कहा कि प्रदेश की जनता राजस्थान में दोबारा सरकार बनाने के मूड में है। उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान को एक पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह बदल गया है। आज, राजस्थान में एम्स, आईआईटी, आईआईएम और अन्य विवि हैं। जब मैं पहली बार सीएम बना, तो केवल छह विवि थे और अब 100 से अधिक कॉलेज हैं।

प्रधानमंत्री मोदी और कमल ही हमारा चेहरा है :गजेंद्र शेखावत

जोधपुर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल ही पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने समाचार एजेंसी एएआई से विधानसभा चुनाव में पार्टी के सीएम चेहरे पर बात करते हुए, कहा, राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी का निशान कमल ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। इसके साथ ही भाजपा के लोकसभा सांसद शेखावत ने यह भी कहा कि पार्टी का संसदीय बोर्ड और विधायक चुनाव जीतने के बाद बैठकर आपस में चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री पद के योग्य नेता का चयन करेंगे। उन्होंने कहा, चुनाव के बाद में विधायक और संसदीय बोर्ड तय करेंगे कि सीएम का चेहरा कौन होगा। चेहरा कोई भी हो, हम यह तय करेंगे कि उनका कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा हो।

दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए हरियाणा जिम्मेदार: आप

नईदिल्ली। पिछले एक सप्ताह से राष्ट्रीय राजधानी की सांसें अटकी हुई हैं। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सोमवार को शहर में गंभीर वायु प्रदूषण के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि राज्य सिर्फ 100 किमी दूर है जबकि आप शासित पंजाब, जहां पराली जलाई जा रही है, 500 किमी दूर है। पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर सरकार से यह आकलन करने को भी कहा कि उसने अपने राज्य में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इससे पहले रविवार को, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि पंजाब में पराली जलाने का दिल्ली पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पड़ता है क्योंकि हवा की कोई गति नहीं होती है। प्रियंका कक्कड़ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि शहर में पिछले आठ वर्षों में सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता देखी गई है और पिछले साल आप सरकार के सत्ता में आने के बाद से पराली जलाने में 50 से 67 प्रतिशत की गिरावट आई है।

भगवंत मान सरकार पर बरसे नवजोत सिद्धू

चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने सोमवार को भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा। चंडीगढ़ में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात के बाद सिद्धू ने मीडिया के साथ बातचीत की। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में बिजली की स्थिति खराब है। पंजाब 30,000 करोड़ रुपये की बिजली औसतन 12 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खरीद रहा है, जबकि बाजार में यह ढाई या तीन रुपये प्रति यूनिट है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीक सीजन में पंजाब 19 या 21 रुपये में बिजली खरीद रहा है। मान सरकार पर निशाना साधते हुए सिद्धू ने कहा कि आपने कहा था कि आप सत्ता में आते ही पीपीए (पावर परचेज एग्रीमेंट) रद्द कर देंगे। इस साल फिर पीएसपीएल (पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) 5000 करोड़ रुपये के घाटे में है... यह एक चरमराती हुई शासकीय व्यवस्था है। यह चरमरा जाएगी और वित्तीय आपातकाल लगना तय है... भगवंत मान केवल अखबार और विज्ञापन के सीएम हैं और कुछ नहीं...।

कांग्रेस-समाजवादी पार्टी में दो फाड़

कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बनेः अखिलेश

भोपाल। गठबंधन के मामले में कांग्रेस और अखिलेश यादव एक नजर नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बात नहीं बनने के बाद दोनों के अपने-अपने दावे हैं। इन सब के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। अखिलेश ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कटनी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस के पास मौका था कि वो छोटे दलों को साथ लेकर एक गठबंधन का संदेश दिया जाता लेकिन वो सोचते हैं कि उनके साथ जनता खड़ी है तो अब उन्हें पीडीए इस बार जवाब देगी।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि पहले से बेहतर परिणाम आएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने पिछले कई वर्षों से काम किया है अगर वही जमीनी हकीकत देखे तो चरम सीमा पर महंगाई है बेरोजगारी है....और जो न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ने प्रदेश को उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचाया जहां तक पहुंचना चाहिए था। तकरार के बीच अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा था कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है - एक ऐसा कदम जो संकेत दे सकता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है।

इससे पहले, सपा ने संकेत दिया था कि वह राज्य में 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ देगी। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जो 2024 में भाजपा से मुकाबला करने के लिए एक साथ आई है। लेकिन यादव का यह बयान कि उनकी पार्टी सभी 80 निर्वाचन क्षेत्रों पर तैयारी कर रही है, यह बताता है कि वह अधिकतम सीटों के लिए अकेले लड़ने या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ कड़ी बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। यादव ने तब निराशा व्यक्त की जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे से इनकार कर दिया, जहां सपा छह निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाह रही थी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर एमपी में विश्वासघात% का आरोप लगाया।

विराट ने सेंचुरी मार ली, प्याज की भी हो गई : प्रियंका

भोपाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची हैं। धार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि उज्जैन में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। उन्होंने कहा कि आपके प्रदेश(मध्य प्रदेश) में हर रोज़ 17 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है... महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब आपके सामने चुनाव है, आप चुनिए की क्या आपको फिर से इन्हें 5 साल देना है कि आप पर भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध बढ़े? उन्होंने कहा कि कल केंद्र के कृषि मंत्री के बेटे का एक वीडियो सामने आया जिसमें हजारों करोड़ की बातें हो रही हैं...वहां अडानी जी सरकार की मदद से एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और देश का किसान एक दिन में 27 रुपए कमा रहा है।

गांधी ने कहा कि ये पूज्य संत कमलदास जी, राजा श्री देवी सिंह जी और बाबासाहेब जी की धरती है। इस पावन धरा पर आकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी दादी इंदिरा जी, नेहरू जी और राजीव जी ने हमेशा आपकी संस्कृति का सम्मान किया। इन लोगों ने कभी भी आपकी संस्कृति बदलने की कोशिश नहीं की। इन लोगों ने आपके लिए वैसी ही नीतियां बनाई, जिससे आपकी मदद हुई और आप आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि बड़े व्यवसायी कुछ भी नहीं बनाते हैं और उन्होंने छोटे और मध्यम व्यवसायों को समाप्त कर दिया है, जिससे राज्य के लोगों के लिए रोजगार समाप्त हो गया है। वस्तु एवं सेवा कर की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे लोगों की महंगाई की समस्या और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण महिलाओं को अपनी पसंदीदा चीजें खरीदने से बचना होगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, %%बीजेपी पूछती थी कि सचिन ने सेंचुरी मार ली, प्याज कब सेंचुरी मारेगी।%% अब, मैं पूछना चाहती हूं, विराट ने सेंचुरी मार ली और प्याज की भी सेंचुरी हो गई (विराट ने शतक बनाया है, और प्याज ने भी)। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि कांग्रेस का इरादा आगामी लोकसभा चुनावों के लिए धन जुटाने के लिए राज्य को एटीएम में बदलने का है। रविवार को एमपी के खंडवा में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस का ध्यान एक परिवार के विकास पर केंद्रित है।

सामना में बोली उद्धव शिवसेना

केंद्र में शासन को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन

मुंबई। विपक्षी गठबंधन इंडिया में लगातार असंतोष की खबरें आ रही हैं। इस पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने सोमवार को कहा कि यह गठबंधन केंद्र में तानाशाही शासन को हटाने के लिए बनाया गया है। राज्यों में राजनीति अलग है। शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया कि इस महीने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक रिहर्सल है। यह भी कहा गया है कि कांग्रेस सभी पांच चुनावी राज्यों (राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम) में एक प्रमुख पार्टी है।

संपादकीय में कहा गया, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और धन के अहंकार को चूर करने के लिए कांग्रेस का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। यह इंडिया गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें पार्टी ने यह भी विश्वास जताया कि इंडिया गठबंधन अगले साल लोकसभा चुनाव जीतेगा।

सामना में आगे कहा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंताएं जायज हैं। गौरतलब है, सीएम नीतीश कुमार ने पटना में पिछले सप्ताह कहा था कि कांग्रेस पार्टी को विपक्षी एकता से कोई मतलब नहीं है। आजकल इंडिया को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। हम सबको एकसाथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में व्यस्त है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन पर कतई ध्यान नहीं दे रही है।

हालांकि, सामना में कहा गया है कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए 28 विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुमार को अपनी चिंता सार्वजनिक रूप से जाहिर नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे सत्ताधारी लोग खुश होंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। ये तीनों विपक्षी भारतीय

गुट के घटक दल हैं। हाल ही में, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस को उनकी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि देश की सबसे पुरानी पार्टी गठबंधन चाहती है या नहीं। सामना में कहा गया, इंडिया गठबंधन का गठन केंद्र में तानाशाही शासन को हटाने के लिए किया गया था और हर कोई इससे सहमत है। राज्यों में राजनीति अलग होती है और राजनीतिक दलों को उसी के अनुसार फैसला लेना होता है।

जिन राज्यों में चुनाव है वहां कांग्रेस प्रमुख पार्टी : संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक समावेशी गठबंधन (इंडिया) में दरार की खबरों को खारिज कर दिया और कहा कि विपक्षी सदस्यों की बैठक विधानसभा चुनाव के बाद होगी। राउत ने विधानसभा चुनावों के महत्व पर जोर दिया, खासकर उन राज्यों में जहां कांग्रेस पार्टी प्रमुख स्थिति में है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां कांग्रेस नंबर वन पार्टी है...अगर हम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं हराएंगे तो लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे करेंगे? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पांच राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होगी।

खेल
प्रमुख समाचार

श्रीलंका ने बोर्ड को बर्खास्त किया, अंतरिम समिति नियुक्त

नईदिल्ली। भारत में वनडे विश्व कप में अपनी टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद श्रीलंका टीम सहित बोर्ड में हाहाकार है। विश्व कप में निराशाजनक अभियान के बाद खेल मंत्रालय ने क्रिकेट शासी निकाय बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है और उसकी जगह एक अंतरिम समिति बना दी है। श्रीलंका ने अपने सात विश्व कप मैचों में से केवल दो जीते हैं, लेकिन सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर है। मेजबान भारत से 302 रन की हार के बाद बोर्ड को नाराज प्रशंसकों की भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने संचालन संस्था श्रीलंका क्रिकेट को देशद्रोही और भ्रष्ट कहा और कहा कि बोर्ड के सदस्यों को इस्तीफा दे देना चाहिए।

मंत्री ने शेष बोर्ड सदस्यों को बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह विश्व कप विजेता पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा की अध्यक्षता में एक अंतरिम समिति नियुक्त की। सात सदस्यीय समिति में रणतुंगा के साथ सुप्रीम कोर्ट के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी शामिल होंगे। सातवें स्थान पर मौजूद श्रीलंका सोमवार को अपने अंतिम ग्रुप चरण मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगा।

श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) के सचिव मोहन डी सिल्वा ने भारत में वनडे विश्व कप में अपनी टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका को गुरुवार को मुंबई में भारत ने 302 रन के बड़े अंतर से हराया था। जिसके बाद टीम सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो गयी है। भारत के खिलाफ श्रीलंका की टीम महज 55 रन पर आउट हो गयी। इसके बाद देश के खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने एसएलसी प्रशासन के सामूहिक इस्तीफे की मांग की थी। रणसिंघे ने एक बयान में इस हार के लिए चयन समिति और एसएलसी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। डी सिल्वा का इस्तीफा खेल मंत्री के आह्वान के बाद आया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 595 अंक उछला निफ्टी 19,400 के पार

नईदिल्ली। मिले-जुले ग्लोबल रुझानों के बीच हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन हरे निशान पर बंद हुए। आज दोनों फ्रंटलाइन इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार बढ़त दर्ज की गई। वैश्विक इक्विटी में आज लगातार तीसरे दिन रिबाउंड देखा गया। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 595 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 181 अंक की बढ़त दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 594.91 अंक यानी 0.92 फीसदी की बढ़त के साथ 64,958.69 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 64,992.54 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 64,617.48 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 181.15 अंक यानी 0.94 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 19,411.75 अंक पर बंद हुआ।

अक्तूबर में ऑटोमोबाइल बिक्री में 12 फीसदी बढ़ोतरी हुई

नई दिल्ली। देशभर में वाहनों की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यात्री वाहन के साथ ही दो पहिया वाहन, कमर्शियल वाहन सहित सभी सेगमेंट में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। फाडा के मुताबिक अक्तूबर 2023 के दौरान कितने वाहनों की बिक्री हुई है। इसकी जानकारी हम आपको इस खबर में दे रहे हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से अक्तूबर महीने में कुल वाहनों की बिक्री में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर करीब 12 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फाडा की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक अक्तूबर महीने में कुल 2117596 यूनिट्स वाहनों की बिक्री हुई। इसमें यात्री वाहन, तिपहिया वाहन, दो पहिया वाहन शामिल हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बिक्री में कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक अक्तूबर 2022 के दौरान देशभर में कुल 2295099 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

भारत कोकिंग कोयले का एक्सपोर्ट मार्केट बना रहेगा

नईदिल्ली। भारत निकट भविष्य में भी सबसे बड़ा कोकिंग कोयला निर्यात गंतव्य बना रहेगा। भारतीय इस्पात संघ (आईएसए) ने यह उम्मीद जताते हुए कहा है कि कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर घरेलू इस्पात उद्योग पर पड़ रहा है। कोकिंग कोयला एक प्रमुख कच्चा माल है जिसका उपयोग इस्पात के निर्माण के लिए किया जाता है। आईएसए के अध्यक्ष दिलीप उम्मेन ने सोमवार को कहा कि भारतीय इस्पात उद्योग विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कोकिंग कोयले के उपयोग के लिए स्थायी रास्ते तलाशने के तरीके और साधन ढूंढ रहा है। हालांकि, यह एक लंबी यात्रा है। वह दिल्ली में आईएसए कोकिंग कोयला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, निकट भविष्य में भारत कोकिंग कोयला निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य बना रहेगा। घरेलू इस्पात उद्योग की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि और चीन के अपने संसाधनों पर अधिक निर्भर रहना इसके प्रमुख कारण हैं।

भारत फोर्ज का दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 51.78% बढ़ा

नईदिल्ली। वाहन उद्योग के विभिन्न उत्पाद बनाने वाली प्रमुख कंपनी भारत फोर्ज का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 51.78 प्रतिशत उछाल के साथ 214.87 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने बीते वित्त वर्ष की समान अवधि में 141.56 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया था। भारत फोर्ज ने शेयर बाजार को बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में परिचालन से एकीकृत आय 3,774.19 करोड़ रुपये रही, जो बीते वित्त वर्ष की समान अवधि में 3,076.39 करोड़ रुपये थी। सितंबर, 2023 तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 3,488.43 करोड़ रुपये रहा, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,885.07 करोड़ रुपये था। भारत फोर्ज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बी एन कल्याणी ने कहा, सितंबर, 2023 तिमाही में कंपनी ने सभी खंडों और क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है।

रिसर्च सेक्टर में निवेश की संरचनात्मक जटिलताएं

अजय छिब्बर

भारत ने अपेक्षाकृत कम बजट में चंद्रमा पर पहुंचने के अभियान में सफलता पाई और यह ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत की चांद पर उतरने की महत्त्वाकांक्षी योजना की सफलता की उपलब्धि महत्त्वपूर्ण है, खासतौर पर इस लिहाज से भी कि इसकी अधिकांश अंतरिक्ष योजनाएं स्वदेश में ही विकसित की गई हैं।

इसका एक प्रमुख कारण यह है कि भारत में अनुसंधान एवं विकास (आरऐंडडी) पर किए जाने वाले सीमित खर्च में भी अंतरिक्ष से जुड़ी पहलों को प्राथमिकता दी गई है। हम अगर अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सराहना करते हैं तो यह लाजिमी है कि हम आरऐंडडी के क्षेत्र में व्यापक तौर पर कम खर्च की समस्या पर भी गौर करें। भारत का आरऐंडडी खर्च वर्ष 2008 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 0.8 प्रतिशत पर पहुंच गया था लेकिन यह उस वक्त के बाद से घटकर जीडीपी के 0.65 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है। इसकी तुलना में चीन अपने जीडीपी का लगभग 2.1 प्रतिशत आरऐंडडी पर खर्च करता है और अमेरिका लगभग 2.8 प्रतिशत खर्च करता है।

दूसरी ओर जर्मनी और जापान आरऐंडडी पर जीपीडी का 3 प्रतिशत से अधिक खर्च करते हैं जबकि इजरायल शोध पर सबसे ज्यादा अपने जीडीपी का 5 प्रतिशत तक खर्च करता है। आरऐंडडी में खर्च किए जाने वाले वैश्विक औसत को देखा जाए तो यह जीडीपी का लगभग 2.2 प्रतिशत है। हालांकि यह सच है कि एक विकासशील देश, अनुसंधान एवं विकास पर कम खर्च करता है क्योंकि इसके पास यह गुंजाइश होती है कि यह अमीर देशों से नई प्रौद्योगिकी ले सके।

हालांकि ऐसा करने के लिए भी कुछ स्तर तक आरऐंडडी की आवश्यकता होती है। जब भारत में हरित क्रांति हुई तब दूसरी जगह तैयार हुए अधिक उपज वाले बीज की किस्में लाने में देश सक्षम हुआ क्योंकि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल इन्हें ढालने का अपना आरऐंडडी बुनियादी ढांचा था।

भारत फार्मा के क्षेत्र में भी सफल रहा क्योंकि इसके पास रिवर्स इंजीनियर फार्मास्यूटिकल्स और जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त शोध क्षमताएं थीं। भारत के आरऐंडडी का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य (18 प्रतिशत), कृषि (13 प्रतिशत), अंतरिक्ष (9 प्रतिशत) और रक्षा क्षेत्र (17 प्रतिशत) में खर्च होता है जबकि 10 प्रतिशत से भी कम औद्योगिक उत्पादन, प्रौद्योगिकी से लेकर परिवहन एवं दूरसंचार क्षेत्र में खर्च होता है।

निश्चित तौर पर यह हैरान करने वाली बात नहीं लगती है जब आप इस बात पर विचार करते हैं कि आरऐंडडी का बड़ा हिस्सा (लगभग 60 प्रतिशत) सार्वजनिक क्षेत्र में खर्च होता है जबकि दूसरी ओर अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास पर किए जाने वाले खर्च में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से भी कम है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का आरऐंडडी खर्च जीडीपी का 0.36 प्रतिशत है जो इसी तुलना में रूस के 0.34 प्रतिशत, अमेरिका के 0.28 प्रतिशत, फ्रांस के 0.27 प्रतिशत, जापान के 0.25 प्रतिशत और इजरायल के 0.07 प्रतिशत से अधिक है।

भारत में आरऐंडडी क्षेत्र के खर्च में कमी सार्वजनिक क्षेत्र नहीं बल्कि निजी क्षेत्र के कम योगदान के चलते बनी हुई है जबकि इस क्षेत्र में आरऐंडडी का बजट बहुत अधिक होना चाहिए। अब सवाल यह भी है कि भारत के निजी क्षेत्र से शोध एवं विकास पर इतना कम खर्च क्यों होता है? हम जानते हैं कि निजी क्षेत्र का आरऐंडडी के जरिये मिलने वाला प्रतिफल किसी सामाजिक प्रतिफल से कम है क्योंकि ज्ञान की सुरक्षा करना इतना आसान नहीं है। इसकी चोरी आसानी से हो सकती है या यह पूरी तरह से गायब भी हो सकता है खासतौर पर अगर यह ज्ञान शोध करने वाले व्यक्ति के पास है। चीन कथित तौर पर प्रौद्योगिकी की चोरी करने में माहिर रहा है लेकिन अमेरिका सहित कई अन्य देशों के पास 150 साल पहले ही ऐसी पाइरेटेड तकनीक थी।

सीएम पद संभालने का नैतिक अधिकार खो चुके बघेल : रमन

रायपुर। महादेव बेटिंग ऐप की वजह से छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आया है। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर उनके नेता को फंसा रही है। कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अगस्त में प्रतिबंध की मांग की थी जनता चुनाव में करारा जवाब देगी। इस बीच केंद्र सरकार ने रविवार को महादेव बेटिंप ऐप समेत 22 अवैध सट्टेबाजी वाले ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ईडी कई महीनों से महादेव ऐप मामले की जांच कर रही है लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि इसे प्रतिबंधित करने में इतना समय लगा।कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र सरकार पर महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगाने में देरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पांच महीने पहले की थी। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने ऐप पर प्रतिबंध लगाने की उनकी शुरुआती मांग के लिए बघेल की प्रशंसा करने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई की। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोग विधानसभा चुनावों में भाजपा को उसके कार्यों के लिए करारा जवाब देंगे। इधर महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल के खिलाफ ईडी की जांच पर प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सब कुछ साबित हो गया है भूपेश बघेल अब सीएम पद संभालने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

मैंने संपूर्ण रायपुर के विकास को ध्यान में रखकर कार्य किया : बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आज टिकरापारा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। इस दौरान अपने विधायक बृजमोहन अग्रवाल का घर-घर में अभिनंदन किया गया। उन्हें फूलों की माला पहनाकर और आरती उतार कर जीत के लिए शुभकामनाएं दी गई।इस अवसर पर लोगों की बीच अपनी बात रखते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पिछले 35 वर्षों से निरंतर वह क्षेत्र के विकास के काम में लगे हुए हैं। टिकरापारा क्षेत्र के वासी खुद गवाह है कि बीते वर्षों में होने वाली तकलीफों से आज टिकरापारा क्षेत्र को निजात मिल चुका है। उन्होंने कहा कि सघन आबादी वाले क्षेत्र में विकास करना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, हमने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी मंशानुरूप हर वो काम कराए जो जनहित के लिए जरूरी थे। मैंने संपूर्ण रायपुर के विकास को ध्यान में रखकर कार्य किया है। कैनाल लिंकिंग रोड का निर्माण भी इसी सोच के साथ कराया है। तेलीबांधा से लेकर टाटीबंध तक नेशनल हाईवे पर भटागांव-टिकरापरा, राजेंद्रनगर-न्यू राजेंद्र नगर, कुशालपुर- चंगोराभाटा के मध्य तीन ओवरब्रिज का निर्माण भी किया गया। इस निर्माण से क्षेत्र के लाखों लोगों की परेशानियां दूर हुई है। दुर्घटनों में भारी कमी आई है। नही तो रोजाना सड़क पार करते वक्त दुर्घटनाएं होती थी लोगों की जान जाती थी। बृजमोहन ने कहा कि रायपुर शहर मेरा परिवार है ऐसे में चुनाव के वक्त में अपने परिवार से साथ और सहयोग की अपेक्षा के साथ कमल फूल छाप में वोट करने और भाजपा की सरकार बनाने के आग्रह के साथ आपके पास आया हूं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिले भाजपा नेता, कहा बस्तर में मतदान के लिए हो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

रायपुर. सांसद सुनील और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की. सुनील सोनी ने कहा, कल पहले चरण का चुनाव है. तीन दिन पहले नक्सलियों ने नारायणपुर जिले के भाजपा उपाध्यक्ष को बाजार के अंदर मौत के घाट उतारा. नक्सली ऐलान कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा इसलिए सभी मतदान कर सकें इसके लिए कड़ी व्यवस्था की जाए.

सांसद सोनी ने कहा, सभी दल के लोग मिलकर मतदाता को लेकर आ सके ऐसी व्यवस्था हो. निर्वाचन प्रमुख से आग्रह किया है कि खून की होली कब तक चलेगी. कल बिना हिंसा के चुनाव हो और इसकी पुनवृत्ति न हो, पुलिस प्रशासन से भी कहूंगा कि सरकार आती है जाती है, भविष्य वक्ता न हो. आने वाले समय में भाजपा की सरकार बन रही है. अपनी वर्दी अगर पहननी है तो ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करें नहीं तो आने वाला समय अच्छा नहीं है. चुनाव को प्रभावित करना देश के नियम कायदे को दरकिनार होने वाले लोग हैं, वह लोकतंत्र के खिलाफ करेंगे.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 'छवि खराब' करने वाले बयान पर सांसद सुनील सोनी ने कहा, हम कहा भूपेश जी की छवि खराब कर रहे हैं. शुभम सोनी आपकी छवि खराब कर रहे हैं. ईडी आप पर कार्रवाई कर रही है. ईडी का मूल काम है प्रदेश और देश के पैसे को खजाने में जमा करना. सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास ईडी नहीं गई. उन चंद लोगों के पास ही क्यों गई, ईडी पहले भी काम कर रही थी और पैसे बाहर निकाल रही थी. उसे ऐसे काम करना ही चाहिए.

मुख्यमंत्री बघेल द्वारा बीजेपी पर लगाए आरोपों पर सुनील सोनी ने पलटवार करते हुए कहा, महादेव एप को पैदा कौन किया और पैदा हुआ कहां से..? आपके गृह जिले से पैदा हुआ है. इसके पैदा होते ही धारा 69 ए का उपयोग कर प्रतिबंधित कर देते, पर उसे आमदनी का जरिया बनाया होगा. देश और दुनिया में फैलाने में शासन प्रशासन का सहयोग हुआ होगा, ये शुभम सोनी ने कहा है. जब देश और दुनिया में आया तब पीएम मोदी ने फैसला लिया कि मेरे देश का नौयुवक इसमें ना फंसे.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनाव से पहले कार्रवाई करने वाले बयान पर सुनील सोनी ने कहा, चुनाव के एक दिन पहले क्या किया. देश की गंदगी और ईडी की कार्रवाई के बाद 508 करोड़ रुपए पकड़ाया. तो प्रमाणित हुआ की देश भर में गंदगी फैला रहा है तो तत्काल बंद कर दिया. चुनाव का क्या संबंध है. देश की चिंता मोदी ने की और प्रदेश की चिंता सीएम को करनी थी.

कांग्रेस के आरोप पर अमर अग्रवाल का पलटवार

बिना प्रमाण के आरोप लगाना कांग्रेस की ओछी मानसिकताः अमर

बिलासपुर. ईडी द्वारा नकदी बरामद करने के मामले में पूर्व मंत्री और बिलासपुर से बीजेपी के प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी है. अमर अग्रवाल ने गाड़ी का दस्तावेज जारी करते हुए कहा कि गाड़ी जून में ही बेची जा चुकी है. अमर ने कहा कि ड्राइवर ने कांग्रेस का नाम लिया. मेरा नाम लेना घोर आपत्तिजनक. बिना प्रमाण के आरोप लगाना कांग्रेस की ओछी मानसिकता है.

बता दें कि कांग्रेस ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाया था. बीजेपी पर निशाना साधते हुए सुशील आनंद शुक्ला ने कई सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि श्वष्ठ ने जिस गाड़ी में करोड़ो रुपये कैश रखकर फोटो जारी किया है, वो गाड़ी भाजपा नेता की है. जिसमें ड्राइवर, कुरियर बॉय, भाजपा कार्यकर्ता सबित हो चुका है.

सुशील आनंद ने बताया कि ऋञ्जह्र में ये गाड़ी सनफ्लॉवर प्रमोटर्स के मालिक बृजमोहन अग्रवाल के नाम पर दर्ज है. जो कि बिलासपुर के पूर्व विधयाक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के भाई हैं. लेकिन श्वष्ठ ने कोई जांच नहीं की. बल्कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगा दिया.

जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना हमारी पहली प्राथमिकताः पुरंदर मिश्रा

रायपुर। चुनाव में जीत के लिए दौरा और जनसंपर्क की कड़ी में रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रविवार को भाजपा मंडल तेलीबांधा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान जहां-जहां श्री मिश्रा का काफिला पहुंचा, वहां-वहां पर स्थानीय लोगों ने अपने नेता का स्वागत किया। भाजपा मंडल तेलीबांधा क्षेत्र की जनता के स्नेह से प्रसन्न श्री पुरंदर मिश्रा ने कहा, मुझ पर विश्वास कीजिए, आप लोगों के माध्यम से सेवा का अवसर मिलने पर पूरे उत्तर विधानसभा क्षेत्र का समुचित विकास किया जाएगा। शहर में बढ़ते अपराध और नशाखोरी की रोकथाम कर यहां की जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। दौरा और जनसंपर्क के दौरान श्री मिश्रा और उनका काफिला सबसे पहले शाम लगभग 4 बजे तेलीबांधा क्षेत्र के मरीन ड्राइव रिंग रोड और मंत्रालय कॉलोनी पहुंचा, जहां से जनसंपर्क की शुरुआत की गई। इसके बाद नई बस्ती, पुरानी बस्ती, सुयोग विहार, अमेय विहार, पप्पू ठाकुर और गोपाल चंद्राकर निवास होते हुए जय जवान चौक पहुंचा। यहां स्थानीय लोगों ने फूलमालाएं पहनाकर श्री मिश्रा का आत्मीय स्वागत किया। इसके बाद यह कारवां सतनामी पारा, साहू बाड़ा, शारदा नर्सिंग होम और हिमाचल आइस फैक्टरी होते हुए महादेव मंदिर पहुंचा, जहां पर कार्यक्रम का समापन हुआ।इस दौरान स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने कहा- भाजपा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए एक-एक वायदे को पूरा करेगी। भाजपा की सरकार वापस बनने पर प्रदेश में महिलाओं व बेटियों के लिए योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा। भाजपा की सरकार बनने पर पीएम आवास योजना के पात्र लोगों को मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी।

भाजयुमो ने निकाली बाइक रैली

रायपुर ।भाजयुमो कार्यकर्ताओं की बाइक रैली सोमवार को शहर में चर्चा का विषय बन गई। भाजपा की बाइक रैली और रोड शो में लगभग 500 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया और भाजपा प्रत्याशी के पत्र में बने माहौल को मजबूती देने के लिए ताकत झोंकी। बताते चलें कि चुनाव में जीत के लिए रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा के पक्ष में प्रचार अभियान जोर-शोर से चल रहा है। इसी क्रम में भाजयुमो के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर में भव्य बाइक रैली निकाली और रोड शो किया। यह रैली जिला महामंत्री अर्पित सूर्यवंशी, आशीष आहूजा और आकाश तिवारी के नेतृव में निकाली गई। बाइक रैली को चुनाव संचालक लोकेश कावड़िया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के लगभग 500 से अधिक कार्यकर्ता 300 से ज्यादा बाइक में सवार होकर निकले। यह रैली राजधानी के रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों से होकर गुजरी। रैली में युवाओं ने गर्मजोशी के साथ नारेबाजी करते हुए रायपुर उत्तर विस क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा को जिताने की अपील की। इन क्षेत्रों में दिखा युवाओं का जोशः बाइक रैली रायपुर रेलवे स्टेशन के हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई, जो गुरुद्वारा रोड होते हुए राजीव गांधी चौक, स्टेशन रोड से गुरुनानक चौक, राठौर चौक, ललिता चौक, फूल चौक, शारदा चौक, एमजी रोड, मौदहापारा, फाफाडीह चौक, साहू पारा, टिम्बर मार्केट, लाल चौक, सिंधु भवन रोड, दुल्हन चौक, पंडरी कपड़ा, प्रमोद साहू के आफिस, लोधीपारा चौक, क्रिस्टल आर्केड, टर्निंग पाइंट, भारत माता चौक, एमडी चौक, समापन किया।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

पहले चरण की सभी 20 सीटें जीतेंगे : दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन, समृद्धि और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के पर्याय बन चुके कांग्रेस की भरोसे की सरकार पर एक बार फिर मोहर लगाने छत्तीसगढ़ के मतदाता तैयार हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल के कामों से छत्तीसगढ़ के लोगो का चहुंमुखी विकास हुआ है। आने वाले पांच सालो के लिये भी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की तकदीर बदलने घोषणा पत्र बनाया है। जनता कांग्रेस सरकार की वापसी के लिये मुहर लगायेगी।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा है कि बस्तर और राजनांदगांव के 20 सीटों में कल प्रथम चरण का मतदान है, जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वादों पर कांग्रेस के वादों पर जनता ने भरोसा किया था उसी तर्ज पर उससे आगे बढ़कर इस बार कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। पिछले 5 वर्षों के दौरान जिस तरह से अपने वादों से बढ़कर भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की बेहतरीन के लिए काम किया है। बस्तर और राजनांदगांव की जनता मतदान के रूप में मतदाताओं का स्नेह और आशीर्वाद कांग्रेस प्रत्याशियों को मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा है कि 2018 का विधानसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के कुशासन भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी को उखाड़ फेंकने के लिए था।

कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र की शिकायत की

रायपुर। कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण, माता सीता और श्री हनुमान जी के स्केच चित्र को हटाये जाने का आदेश प्रदान करने बाबत् शिकायत में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में आचार संहिता लागू है। ऐसी स्थिति में बीजेपी की घोषणा पत्र, छत्तीसगढ़ के लिये, मोदी की गारंटी 2023 के शीर्षक पृष्ठ 3 पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित लेख के उपर दर्शित भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण, माता सीता और श्री हनुमान जी को स्केच चित्र के आधार पर नेत्रहीन दिखाया गया है। साथ ही उक्त घोषणा पत्र के 33 वें पृष्ठ में मंदिर की फोटो दर्शित है। हम सब के आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम जिन्हें हम आदर्श के साथ और श्रद्धा से कमल नयन भी कहते है ऐसी स्थिति में बीजेपी के घोषणा पत्र में भगवान श्री राम जी को नेत्रहीन दिखाया जाना हम सब के आस्था के विरूद्ध है और आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। जिसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा उक्त को तत्काल हटाये जाने का आदेश प्रदान करने की आवश्यकता है।अतः निवेदन है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण, माता सीता और श्री हनुमान जी की स्केच चित्र और पृष्ठ 33 वें में दर्शित मंदिर की फोटो को तत्काल हटाया जाये और बीजेपी के विरूद्ध समुचित कार्यवाही किया जाये। उक्त कार्यवाही के संबंध में अवगत कराये जाने की कृपा करें। ज्ञापन सौंपने वाले में कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. देवा देवांगन, नंद कुमार पटेल, कहकसा दानी, महेन्द्र देवांगन, राम शंकर सोनकर, रमेश शर्मा, ललित कुमार सोनी, सलीम खान, सादिक अली, मनोज सोनकर, अंकित कुमार मिश्रा, विजय कुमार राठौर, बंटी पटेल उपस्थित थे।

ईडी ही भाजपा है और भाजपा ही ईडी हैः शुक्ला

रायपुर। राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ईडी ही भाजपा है और भाजपा ही ईडी है। भाजपा की केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता तथा ईडी ने मिलकर छत्तीसगढ़ के चुनावों से जनता का ध्यान भटकाने प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का षड़यंत्र रचा है। भाजपा के कार्यकर्ता के बयान पर ईडी आरोप लगाती है भाजपा नेता के भाई की गाड़ी से कैश जप्त होता है, भाजपा अपने दफ्तर से वीडियो जारी करती है यह रिश्ता क्या कहलाता है?ईडी एक ड्राइवर (कैश कुरियर) को पकड़ती है उसके बयान के आधार पर प्रेस नोट जारी करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर महादेव एप्प से 508 करोड़ रू. लेने का आरोप लगाती है। फिर इसी के संदर्भ में ईडी महादेव एप्प के एक कर्मचारी शुभम सोनी का एक सपोर्टिंग मेल का हवाला देकर इस आरोप की पुष्टि करवाती है।दूसरे दिन भाजपा के कार्यालय से एक वीडियो जारी होता है जिसमें एक शुभम सोनी नाम का व्यक्ति खुद को महादेव एप्प का मालिक घोषित करता है तथा अभी तक महादेव एप्प के चर्चित मालिक सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल को कर्मचारी बताता है। शुभम सोनी के इस वीडियो को भाजपा ने क्यों रिलीज किया? भाजपा के पास कहां से आया? यदि यह वीडियो शुभम सोनी ने भाजपा को भेजा है।

सरकार महादेव ऐप को अधिकार रहते नहीं किया बैन : सिद्धार्थनाथ

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मीडिया संयोजक और प्रयागराज के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि महादेव एप पर प्रतिबंध के सवाल को लेकर उन्होंने (श्री सिंह ने) स्वयं पत्रकारों को प्रेस वार्ता में दो-तीन दफे बताया है कि राज्य सरकार को महादेव एप को बैन करने का अधिकार दिया हुआ है। कल भारत सरकार ने महादेव एप एवं अन्य को बैन किया है। श्री सिंह ने कहा कि मैंने उस समय भी बताया था कि कुछ कारणों से केंद्र सरकार इसको बैन कर सकती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल सुरक्षा, कोई रक्षा से संबंधित हो, कोई डाटा चुरा रहा हो या फिर टेररिज्म का कोई विषय आता है।भाजपा के केंद्रीय मीडिया संयोजक और विधायक श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने भी कल स्वयं कहा है कि 2 साल से राज्य की कांग्रेस सरकार महादेव एप की जांच कर रही थी। प्रदेश सरकार के पास कानून था 69-ए का कि वह इस महादेव ऐप को बैन कर सकती है लेकिन प्रदेश सरकार ने बैन नहीं किया और जब बैन नहीं किया और न ही उसने केंद्र सरकार को कोई रिक्वेस्ट भेजी। यह दोनों चीज कही है। 69-ए के तहत प्रदेश सरकार को अधिकार था जो दिया जाता है, या वह केंद्र को लिखकर भेजती हैं। जब मुख्यमंत्री बूपेश बघेल ने नहीं किया तो ईडी ने केंद्र को चिट्ठी भेजी कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है और मनी लांड्रिंग के अंदर टेररिज्म मनी लॉण्ड्रिंग भी होती है, केंद्र सरकार ने इसको बैन किया है। अब यह साफ हो गया कि हम जो कह रहे थे।

संकल्प पत्र कांग्रेस की सत्ता से विदाई का दस्तावेजः मरकाम

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी अनसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को लूटा और छला है। कांग्रेस के शासनकाल में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ क्षेत्र में तेंदूपत्ता नदियों में बहाया गया और आंध्र व ओड़िशा के ठेकेदारों को औने-पौने दाम पर बेचा गया। प्रदेश की भूपेश सरकार ने आदिवासियों के हरे सोने को काला सोना बनाकर रख दिया। श्री मरकाम ने कहा कि पिछले पाँच वर्षों के कांग्रेसी कुशासन ने छत्तीसगढ़ को फिर बदहाली के मुकाम पर ला खड़ा किया है। अब चूँकि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसलिए भाजपा ने विकास के संकल्प के साथ अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जनजातीय क्षेत्रों में भाजपा ने सबसे अहम संकल्प यह व्यक्त किया है कि भाजपा की सरकार बनने पर तेंदूपत्ता संग्राहकों को 4,500 रुपए बोनस और चरणपादुका के साथ-साथ वे सारी सुविधाएँ फिर से मुहैया कराई जाएंगीं, जो भाजपा की पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार के कार्यकाल में दी जा रही थीं और कांग्रेस की आदिवासी विरोधी सरकार ने जिन्हें बंद कर दिया था। भाजपा अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मरकाम ने सोमवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों से कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर तेंदूपत्ता संग्राहकों से अब 2,500 रु. से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदा जाएगा।

'सत्ता' के लिए सट्टा पर सियासतः सीएम भूपेश का सियासी प्रहार, बोले-

ईडी और भाजपा में बढ़िया संबंध, दोनों मिलकर महादेव एप वालों को बचा रहे

रायपुर. छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल के बीच महादेव एप पर सियासत लगातार जारी है. भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे पर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. इस बीच सीएम बघेल ने भी महादेव एप को लेकर भाजपा और ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सीएम बघेल ने कहा, 17 तारीख तक कुछ ना कुछ आता रहेगा, जब तक मतदान नहीं होगा. ईडी और बीजेपी मिलकर महादेव एप वालों को बचा रहे हैं. अभी भी सट्टा एप बंद नही हुआ है. क्क्र चल ही रह है, उसे कब बंद करेंगे? वीडियो ब्क्चक्क ने जारी किया और प्रेस नोट श्वष्ठ ने जारी किया. दोनों में बढ़िया संबंध हैं. श्वष्ठ और भाजपा की मिली भगत स्पष्ट हो गया है.

आगे भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी हार मान चुकी है. ईडी प्रमुख भूमिका निभा रही है. जो पकड़ा गया वो बीजेपी का करीबी है, जो गाड़ी पकड़ी गई वो भी बीजेपी के नेता की गाड़ी है. अभी तक सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल को मुख्य आरोपी मान रहे थे.

भूपेश बघेल ने कहा, आरोप लगाना हैं मैं भी लगा देता हूं. ईडी और बीजेपी मिलकर महादेव एप वालों को बचा रहे हैं.

दो साल से इसकी जांच चल रही है, बीजेपी की मंशा इसे बंद कराने की नहीं है. इस पर कार्रवाई करनी चाहिए. जब तक ऑनलाइन बैटिंग बंद नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा. हमने 3 से 4 हजार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराए हैं.

भूपेश बघेल ने आगे यह भी कहा, इन सबसे बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिल रहा है. जब तक ऑनलाइन बैटिंग बंद नहीं होगा यह सब बंद नहीं हो सकता है. केंद्र सरकार को इन सब को बंद करना चाहिए. बीजेपी को छत्तीसगढ़ का खजाना और खदान चाहिए, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं. वीडियो वाला व्यक्ति पहले अपने आप को महादेव सट्टा ऐप का कर्मचारी बता रहा था और बाद में खुद को महादेव का मालिक बता रहा है. अब तक हमने 400 एफआईआर दर्ज कराई है. केंद्र सरकार ने क्या किया है. लुक आउट सर्कुलर हम जारी कर चुके हैं, ये पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है.

सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूंः महन्त

रायपुर। जब मैं मठ मंदिर में रहता हूं तब भगवान रघुनाथ जी, बालाजी और हनुमान जी की सेवा में तल्लीन रहता हूं लेकिन मठ मंदिर के चार दिवारी से निकल करके जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता हूं। यह बातें रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज ने जनसंपर्क के दौरान अभिव्यक्त की उन्होंने कहा कि सेवा ही हमारा धर्म है सेवा ही हमारा कर्म है ।हम मठ मंदिर में रहकर लोगों की सेवा ही तो करते हैं। पामगढ़ एवं जैजैपुर में दो बार मैंने विधायक के रूप में जनता जनार्दन की सेवा की है, मुझे उत्कृष्ट विधायक के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है। लोगों को महापौर एजाज ढेबर ने संबोधित करते हुए कहा कि- महाराज जी जैसे स्वच्छ छवि के व्यक्ति को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है एक ओर सेठ है और दूसरी ओर संत निर्णय आपको करना है। सभापति प्रमोद दुबे ने कहा कि- महन्त रामसुन्दर दास जी वे शख्सियत हैं जिनसे मिलने के लिए देश के अनेक राज्यों के लोग उनसे समय की याचना करते हैं, आज वे ही हमारे बीच में हमें दर्शन देने के लिए उपस्थित हुए हैं, यह हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में कन्हैया अग्रवाल, अजय तिवारी, दाऊ महेंद्र अग्रवाल, पार्षद जितेंद्र अग्रवाल,जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता शर्मा, प्रशांत ठेंगड़ी, सचिन शर्मा, सतनाम सिंह पनाग , अनिल तिवारी, सत्यनारायण नायक, अनिल बरोड़िया, बन्शी कन्नौजे, भूपत महोबिया ,लालू गोस्वामी सहित कांग्रेस के प्रांतीय निरंतर साथ चल रहे हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.